REPORT OF THE DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY, ENVIRONMENT AND FORESTS

SYED SIBTEY RAZI: (Uttar Pradesh): Madam, I present the Twentieth Report (in English and Hindi) of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Science and Technology, Environment and Forests on the Annual Report (1993-94) of the Department of Ocean Development with reference to Marine Satellite Information Service (MARSIS); Pollution Monitoring programme-Coastal Ocean Monitoring and Prediction System (COMAPS) and National Programme for Identification of Marine Bioactive Substances for use as Drugs.

REPORTS OF THE STANDING COMMITTEE ON FINANCE

SHRI SATISH AGARWAL (Rajasthan): Madam Deputy Chairperson, I lay on the Table a copy each (in English and Hindi) of the following Reports of the Standing Committee on Finance:

(i) Eleventh Report on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the Fifth Report of the Committee on 'Demands for Grants (1994-95) of the Ministry of Finance'.

(2) Twelfth Report on Action Taken by the Government on the recommendation contained in the Sixth Report of the Committee on 'Demands for Grants (1994-95) of the Ministry of Planning and Programme Implementation.

(3) Thirteenth Report on Demands for Grants (1995-96) of the Ministry of Finance.

(4) Fourteenth Report on Demands for Grants (1995-96) of the Ministry of Planning and Programme Implementation.

REPORTS, RECORDS OF DISCUSSIONS AND MINUTES OF THE STANDING COMMITTEE ON ENERGY

SHRI RAJNI RANJAN SAHU: (Bihar): Madam, I lay on the Table a copy each (in English and Hindi) of the following Reports, Records of the discussions and Minutes of the Standing Committee on Energy:—

(i) Twentieth Report on the Ministry of Power—Demands for Grants (1995-96) and record of discussion relating thereto.

(ii) Twenty First Report on the Ministry of Coal—Demands for Grants (1995-96) and record of discussion relating thereto.

(iii) Twenty Second Report on the Ministry of Non-con-ventional Energy Sources—Demands for Grants (1995-96) and record of discussion relating thereto.

(iv) Twenty Third Report on the Department of Atomic Energy Demands for Grants (1995-96) and record of discussion relating thereto.

(v) Minutes of sittings of the Standing Committee on Energy relating to procedural and miscellaneous matters.

REPORTS OF THE STANDING COMMITTEE ON DEFERENCE

SHRI S. JAIPAL REDDY: (Andhra Pradesh): Madam, I lay on the Table a copy each (in English and Hindi) of the following Reports of the Standing Committee on Defence:—

(i) Third Report on action taken by Government on the recommendations contained in their Second Report on Demands for Grants of the Ministry of Defence for 1994-95.

(ii) Fourth Report on the Demands for Grants of the Ministry of Defence for 1995-96.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Deepening crisis in the Handloom industry resulting into under employment and Unemployment of Handloom weavers leading to starvation etc. and the action taken by the Government thereto.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Kotaiahji, I must say that your Calling Attention is very important and it should be discussed, but we have to finish the Calling Attention before lunch. So, we have one and a half hours, till 1.30. Kindly make your points and I request the others also to put questions only and not to make long speeches so that there is enough time for the Minister to answer. You call the attention first and then the Minister will make his statement.

SHRI PRAGADA KOTAIAH (Andhra Pradesh): Madam, the Minister is making a statement in advance.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Yes. First, you call the attention and then the Minister will make a statement.

SHRI PRAGADA KOTAIAH: Madam, I beg to call the attention of the Minister of Textiles to the deepening crisis in the handloom industry resulting in underemployment and unemployment of handloom weavers leading to starvation etc. and the action taken by Government in regard thereto.

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकटस्वामी) जो देश में हैंडलूम वीवर्स की पोजिशन ठीक नहीं है, उस सिलसिले में श्री प्रागदा कोटिया जी ने कॉलिंग अटेंशन दिया है। कुछ बातें मैंने अपनी स्पीच के द्वारा उनको पहुंचा भी दी हैं और कुछ पोइंट्स मैं उनके सामने रखना चाहता हूं। उपसभापति महोदय, हमारे.... **(व्यवधान)**

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार): स्टेटमेंट को अच्छा टाईप होना चाहिए था, पढ़ने में नहीं आ रहा है।

उपसभापति: मंत्री जी, अपने मंत्रालय में फोटो कॉपी मशीन ले लीजिए। अभी तक साइक्लोस्टाइल चल रही है। कॉपी अच्छी नहीं आई है।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): मशीनरी उतनी ही पुरानी है, जितने मंत्री जी पुराने हैं।

श्री चतुरानन मिश्र: आप 1857 वाला रखें।

उपसभापति: सुना था कि आपकी एक्जीबिशन इतनी मॉडर्न थी, कम्प्यूटर वगैरह लगा था।

SYED SIBTEY RAZI: (Uttar Pradesh): Mr. Minister, would you yield for a moment? Madam, the Minister has already circulated his statement. Now, he is making a speech. If he makes a speech in the very beginning, I think we will not be able to conclude the Calling Attention Motion before lunch. My request to the Minister is, he should read out the statement and on the basis of that statement the hon. Members would put questions and the Minister would reply. If he makes a long speech now, I think we will not be doing justice to the hon. Member who has moved the Calling Attenion Motion. Let him read out the statement (Interruptions).

उपसभापति: आप सब लोग बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी।

श्री जी. वेंकटस्वामी: मैं ऑनोरेबिल मेंबर को इसलिए बतलाना चाहता हूं कि जो भी है आप बोलिए, मुझे जो देना था वह अपना ऑपिनियन आपके सामने रखा है। आप बोलिए, टाईम कम है। मैं जवाब में पूरा कवर करूंगा।

उपसभापति: दैट इज बैटर, मंत्री जी, एक मिनट आप बैठिए। मैं बताऊं। जब कॉलिंग अटेंशन आता है तो उसके लिए हमारे यहां स्टेटमेंट आता है। हमको यह भी मालूम है कि आपका कॉलिंग अटेंशन अर्जेंटली आया, कल आना चाहिए था। तो आपको समय भी नहीं मिला। हो सकता है इसलिए

आपको फोटो कॉपी बराबर नहीं मिली है । आई अंडरस्टेंड दैट प्रोब्लम ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : (उत्तर प्रदेश) : हिन्दी वाला भी नहीं मिला ।

उपसभापति : हां, हिन्दी का भी नहीं मिला । इसलिए वह हिन्दी उर्दू में बोल रहे हैं । हिन्दी बहुत अच्छी बोलते हैं । अगर हम तकरीर करेंगे तो उसमें से लोगों को पोइंट्स नहीं मिलेंगे । आपका स्टेटमेंट होगा, तो हमारे एम. पीज. पोइंट्स लेकर उस पर आपसे सवाल कर सकते हैं । चूंकि मैंने कहा कि सवाल पूछें, भाषण नहीं करना है । स्टेटमेंट काफी लम्बा है । आप इसके लिए खास-खास पोइंट्स बोलना चाहते हैं जो अहम् मुद्दे हैं । वह आप बोल दीजिए और फिर लोग पढ़कर उस पर सवाल कर लेंगे । कोटैया जी, जो बोलना चाहते हैं उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा । वह तो बोलेंगे जो उनको बोलना है । कोटैया जी, अपनी बात बोलेंगे । आप उनकी फिक्र मत कीजिए । आप जो बोलना चाहते हैं उसके बाद बोल लीजिए ।

श्री जी. वेंकटस्वामी : उपसभापति महोदया, देश की यह बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है, आफ्टर एग्रीकल्चर लेबर । हमारे देश में गरीब वर्किंग क्लास हैंडलूम वीवर्स हैं जो बिलो पावर्टी लाइन के नीचे जी रहे हैं और कई साल से इन लोगों की हालत को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट आफ इंडिया ने कोशिश की है । मगर उपसभापति महोदया, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि इस मिनिस्ट्री को लेने के बाद जनवरी, 1993 के बाद मैंने पूरे हिन्दुस्तान के वीवर्स की एक मीटिंग बुलाई और सारे लोगों ने आकर वहां अपनी-अपनी मुश्किलात को जाहिर किया । उपसभापति महोदय, सब से बड़ा मुश्किल था उनको हैंक यार्न सप्लाई का मामला । जब तक कि वीवर्स के हाथ में हैंक यार्न सप्लाई नहीं होगा, तो वह जी नहीं सकते । उसी लिहाज से कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से उन लोगों का मियां बीबी का इंकम तीन सौ रुपए मंथली बताया गया । जबकि बिलो पावर्टी लाइन से ऊपर इन्हें उठाने का हमारा जो टारगेट है । इसके लिए हमारे ऑनोरेबिल प्राईम मिनिस्टर ने खास तौर से कहा कि—तुमको इस मिनिस्ट्री में लाया गया है तो कुछ करके बताओ और तुम, वीवर्स की मुश्किलात को दूर करो । मैं आपकी जानकारी में लाना चाह रहा हूं इनको मदद करने के लिए हमने तीन हजार हैंडलूम डवलपमेंट सेंटर कायम करने का लक्ष्य रखा ताकि यार्न सप्लाई हो, ताकि वह लोग जी सकें और वह लोग काम कर सकें । इस तरह से हमने वह कायम किया । उसी लिहाज से हमने 500 सेंटर डाइज के कायम करने का लक्ष्य रखा, ताकि उनको डाइज पक्के मिलें और उसके बाद वह काम कर सकें । उस लिहाज से मैं आपको यह बताना चाह रहा था कि :

"The overall production in the handloom sector had increased from 4,123 million sq. meters in 1991-92 to 5,851 million sq. meters in 1993-94."

इसका नतीजा यह है कि इंक्रीज जो हुआ है यह करने से, वह मैं आपको बतला रहा हूं ।

"Employment which was 87.96 lakh persons in 1991-92 had increased to 116.20 lakh persons in 1993-94."

यह मदद करने की वजह से उन लोगों की जो प्रोडक्टिविटी है वह इनक्रीज हुई है । The value of export of cotton handloom cloth has increased from Rs. 689.19 crores in 1991-92 to about Rs. 1500 crores—provisional—during 1994-95. ये ऐक्सपोर्ट के अंदर काफी आगे बढ़ चुके हैं । जो इम्पॉर्टेन्ट बात है, वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ।

SHRI VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): He is actually reading from some other paper.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You did not follow what I said because I spoke in Hindi. The statement that he has given is a long statement and as we have to finish it in 1½ hours, I suggested that he give the salient points of his statement. The statement is before you. You can read it and ask questions on the subject. He will mention the important points now so that we can finish it in 1½ hours.

श्री जनेश्वर मिश्र (उत्तर प्रदेश) : क्या इन्होंने यह स्टेटमेंट हाउस में ले कर दिया है टेबल पर ?

THE DEPUTY CHAIRMAN: It has been laid on the Table of the House.

श्री जी० वेंकटस्वामी : उपसभापति जी, यह पहले से बन्ध फाइव ईयर प्लान में तो 131 करोड़ रुपया ही प्लान मद में था। सभी प्लान और नॉन प्लान मिल करके 1130 करोड़ था, सेवन्थ फाइव ईयर प्लान कंप्लीट होने तक। उसको ले जा कर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसमें काफी इंटरेस्ट लिया। अभी लगभग कुल 2840 करोड़ (प्लान, नानप्लान और बैंक क्रोडर मिलाकर) आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्लान बना कर, नई-नई स्कीमें बना कर स्टेट गवर्नमेंट्स को सप्लाई किया है और सेंटर्स कायम करके वीवर्स की जो मुश्किलात है, उनको दूर करने की पूरी कोशिश की है। एक ही मर्तबा नहीं बल्कि कई दफा मिनिस्टर्स कान्फ्रेंस बुला कर हमने कहा कि हम ये स्कीम्स देने के लिए तैयार हैं, आप इंप्लिमेंट कीजिए। इंप्लिमेंट करने के लिए बहुत सारे स्टैट्स आगे आ रहे हैं, इंप्लिमेंट होते जा रहे हैं। मैं नहीं समझता कि इसके बावजूद भी अगर कोई मुश्किलात हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तैयार है वीवर्स के अपलिफ्टमेंट के लिए। उनकी जो रोजगारी है, उसको किस तरह से बढ़ाया जाए ? मैं आपको बताना चाहता हूं कि हैंडलूम वीवर्स को जो मौजूदा कंडीशन है, इन सारी स्कीम्स को अगर सही तरीके से इंप्लिमेंट किया जाए स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा तो उनकी जो गरीबी है, उस गरीबी को दूर करने में काफी मदद मिल सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स को अगर वे इंप्लिमेंट करें। मेरा जहां तक ख्याल है उपसभापति जी कि स्टेट्स ने एक साल पहले तो ज्यादा स्कीम्स ली नहीं लेकिन इस साल में कह सकते हैं कि हरेक स्टेट आगे आ रही है इन स्कीमों को लागू करने, इंप्लिमेंट करने की तरफ जा रही है। मैं आपको यह बता नाचाह रहा था कि ये 3000 सेंट्स, हैंडलूम डेवलपमेंट सेंटर्स कायम होने से उनको जो हैंकयर्न सप्लाई होती है, डाइ सप्लाई होती है तो वे अपने कदमों पर खड़े होकर अपने हैंडलूम क्लॉथ को प्रोड्यूस कर सकते हैं और जी सकते हैं। अभी मैं आपके समने यह रखना चाह रहा था। कई स्कीमें हैं हमारी, मैं उनकी एक लिस्ट अपनी स्वीच के अंदर रख रहा हूं। कई स्कीमें हैं उनकी, वेलफेयर स्कीम हैं, हाउसिंग स्कीम है वर्कशॉप कम हाउस स्कीम है और इतना ही नहीं है बल्कि इंश्योरेंस स्कीम भी है। इन सारी स्कीमों को लागू करते हुए उनकी गरीबी को किस तरह से दूर किया जाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट गवर्नमेंट्स के जरिए से दूर करने के लिए काम शुरू किया है। और मैं समझता हूं कि बहुत हद तक काम शुरू हो चुका है और इस साल और अगले साल पूरे देश के अंदर इन हैंडलूम स्कीम्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है, उसको पूरा करने में हम कामयाब हो सकते हैं। यह सही है कि हमारे पूरे हाउस के मैंबरों की सिम्पैथी पूरी तरह से हैंडलूम वीवर्स के प्रति है। हमने जो काम शुरू किया है, उसके बारे आप जा सकते हैं, वीवर्स से पूछ सकते हैं कि उनको कुछ मदद मिल रही है या नहीं मिल रही है और उसके लिए कोऑपरेटिव सोसायटी के अंदर जो कवर्ड है, उनको तो डायरेक्ट राज्य सरकार के माध्यम से जाता है पैसा मगर जो सोसायटी के अंदर कवर्ड हैं, वह सिर्फ 23 परसेंट हैं। बाकी वीवर्स बाहर हैं। सोसायटी के मेंबर नहीं हैं। हम हरेक स्टेट गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा आता है उसे थ्रू कोऑपरेटिव सोसायटी खर्च करना चाहिए थ्रू कोऑपरेटिव सोसायटी उनको मिलना चाहिए। बहुत सारे स्टेट्स कोऑपरेट कर

रहे हैं, मैं यह नहीं कहता कि कोऑपरेटिव नहीं कर रहे हैं मगर नई सोसायटी बनाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा वीवर्स तक पहुंचाने में जितनी स्पीड से हम जाना चाहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट उस हद तक नहीं जा रही है, इसका मुझे अफसोस है । इसका मुझे अफसोस है । अगर वह किया तो पूरे देश के अंदर वीवर्स के लिए पूरी मदद होगी—अगर गवर्नमेंट आफ इंडिया की स्कीम इम्पलीमेंट हुई तो उनकी गरीबी दूर करने में कोई बाधा नहीं होगी । आनरेबल मेंबर श्री कौटेया यह बहुत सीनियर मेंबर हैं और मैं जानता हूं कि उनका जितना एक्सपीरियेंस इस फील्ड में है, मैं नहीं समझता कि हमारे साउथ में किसी को इतना एक्सपीरियेंस है । मैं यह मानते हुए कहता हूं कि वे इतनी स्कीमें लाकर शुरू करने की बात करते हैं और मेरे से आकर बोलते हैं कि कुछ काम नहीं हुआ । उनका काम करने का जो तरीका है इतना करने के बावजूद और कुछ करने की वे मांग करते हैं । मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि उनकी जो भी मांग है उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट आफ इंडिया कोशिश कर रही है कि किस तरह के उपाय करके उन स्कीमों को इम्पलीमेंट किया जाए ।... **(व्यवधान)**

अब रहा इस कालिंग अटेंशन की बात तो अगर इसमें भी उन्होंने कोई नया प्वाइंट दिया कि किस तरह से वीवर क्लास को ऊपर लाया जाय तो हम उस पर विचार करेंगे । मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया तकरीबन 2800 करोड़ रुपया आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्लान, नानप्लान और बैंक बोर्ड के अन्तर्गत खर्च करेगी, उनकी बहबूदी के लिए उनके अपलिफ्टमेंट के लिये उनके वेलफेयर के लिए । यह पैसा हर एक स्टेट को दे रहे हैं । उपसभापति महोदय हमारी स्कीम केवल इतनी ही नहीं है । हमारा जो हैंडलूम का एक्सपोर्ट है, जैसा कि मैंने अभी बताया पहले यह बहुत कम था । लेकिन अब टोटल एक्सपोर्ट हमारी टैक्सटाइल का 38 हजार करोड़ रुपये हो चुका है । यह मेरे चार्ज लेने से पहले 14 हजार करोड़ रुपये था । पूरा एक्सपोर्ट जो इंडिया का होता है उसमें से एक तिहाई हमारे टैक्सटाइल मिनिस्ट्री से होता है । अब हमारा बाइलैटरल एग्रीमेंट अमेरिका और यूरोप के देशों से हुआ है । उपसभापति महोदया उसके बाद हैंडलूम...

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): What is the break-up of the handloom exports?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Don't interrupt him. You are going to put your questions anyway.

SHRI G. VENKAT SWAMY: I will answer all your questions.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The Minister will answer all your questions at the end of the discussion.

श्री जी० वेंकटस्वामी : उपसभापति जी, बाइलैटरल एग्रीमेंट अभी नया हुआ है आफ्टर गैट, अमेरिका और यूरोप के देशों ने हैंडलूम से कोटा हटा दिया है । जितना चाहों, हैंडलूम अमेरिका और यूरोप के जितने कोटा सिस्टम के कन्ट्रीज हैं, वहां जा सकता है । हमारा प्लान है, गवर्नमेंट आफ इंडिया का जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनकी और हैंडलूम वीवर्स की कांग्रेस बुलाकर उनको जिस तरह का कपड़ा चाहिए एक्सपोर्ट के लिए यह काम अगर उनको मिल जाए तो वीवर्स को जो वेजेज आज मिल रहे हैं, उससे चार गुना ज्यादा उनको वेजेज मिल सकता है । इसके लिए मैं एक कांफ्रेंस बुला रहा हूं । मैं एक्सपोर्ट ओरियेन्टेड हैंडलूम क्लाथ के लिए कोशिश कर रहा हूं । अगर हमारा यह काम शुरू होता है तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा वेज मिलेगा और उनकी खुशहाली बढ़ेगी । गवर्नमेंट आफ इंडिया का इटेंशन है कि उनको हैंकयार्न बराबर पहुंचे, उनको डाइज बराबर पहुंचे और उनको बैंकों की सहूलियत नाबार्ड की सहूलियत मिलती रहे । यह सब सहूलियतें उनको दिलायी हैं और उनको कह रहे हैं कि आप अपने तौर पर हैंडलूम इंडस्ट्री जो हैं उसको आगे लाने की कोशिश करें । हमारी एक्सपोर्ट की तीन चीजें हैं । पहली है हैंडलूम, दूसरी है पावरलूम और तीसरी है मिल के उत्पाद

इंडस्ट्री में तो कम प्रोडक्शन हो रहा है। हमारे देश में टोटल प्रोडेक्शन में 72 परसेंट पावरलूम पैदा करता है। पावरलूम में करीब करीब 64 लाख वरकर्स काम कर रहे हैं और अभी हाल में इज्जतगंज में जाकर मैं वहां के वीवर्स, वहां के हैंडलूम वरकर्स को मिला। वहां इन वरकर्स की हालत बहुत खराब है। वहां पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट लागू नहीं करते। यह उनको लागू करना चाहिए। यह हमने उनसे ख्वाहिश जाहिर की है। अब इस हैंडलूम सबजेक्ट पर कालिंग अटेंशन जो कोटैया जी ने दिया है, जो इस बारे में जो आनरेबल मेंबर्स पूछेंगे उनका जवाब में आखिरी में आपकी परमीशन से दूंगा।

SHRI PRAGADA KOTAIAH: Madam Deputy Chairman, I thank you for giving me an opportunity to initiate a discussion on the vital problem affecting millions of self-employed people in the country. I have gone through the statement made available to the Members by our hon. Minister of Textiles. I thank him very much for the interest he has been taking for the development of the handloom industry. But I am sorry to mention that the Ministry of Textiles has given inflated, exaggerated figures regarding the provision of employment to handloom weavers. It is especially to cover up its failure to supply the required hank yarn to the handloom weavers.

Madam, this is the Annual Report of the Ministry of Textiles. In page 69 of the report, the Ministry has stated that the deliveries of cotton yarn were of the order of 1,272 million kilograms. As per the Hank Yarn Obligation Order. 636 million kilograms of hank yarn should have been made available to the handlooms. But only 366 million kilograms of yarn was made available. According to the reports of the Indian Cotton Mills Federation and also the Planning Commission which must have been available with the Ministry of Textiles, one-third of the hank yarn available in the market is taken away by the powerlooms for colouring and for producing coloured cloths. Apart from that, hank yarn is used for fishing nets, ropes, sewing threads and ball threads. No data is available regarding the portion of hank yarn used by all these agencies. Even if we agree with the Government that the entire hank yarn delivered in the market, including the 42 million kilograms of non-cotton yarn. was used by the handlooms, the cloth production would have only been of the order of four thousand million metres. Then how is that the Government has come to the conclusion that the handloom cotton cloth has been increased to 5851 million metres of cloth of yarn? There is no use giving an exaggerated figure of either the provision of employment or the production of handloom cloth and trying to deceive not only the handloom weavers but also the people of this country.

Madam, as the time available is very short, I would not like to go into the details. The Minister has referred to several schemes for the development of the handloom industry. I would only refer to one particular scheme. When there were 165 starvation deaths in Andhra Pradesh in the year 1991-92, the Government said that it would insure the lives of the handloom weavers in all those areas. The premium was Rs 120/-. The Government said that the entire premium would be paid by it. The amount of insurance was Rs. 10,000/-. Subsequently, the Government said that 50 per cent of the premium should be paid by the State Government. After some time, the Government of India said that one-third would be paid by it, i.e. Rs. 40/-, one-third should be paid by the State Government and the remaining one-third should be paid by the handloom

(Shri Pragada Kotaiah)

weaver concerned. The peculiar condition of the scheme is that the families of those handloom weavers who die before the age of 60 are entitled to get the insurance amount of Rs. 10,000/-. We have been suggesting to the Government that the people will live beyond 60, those men should receive the amount paid by the State Government, the amount paid by the Central Government and the amount paid by the weaver together with the accrued interest. For getting an insured amount of Rs. 10,000, the Government wants the weaver to die before the age of 60. See, this is how the scheme is working.

He has been referring to the handloom development centres. What is the Centre? They have announced that 250 looms providing employment to 1,000 people will be given, loans and grants Rs. 27 lakhs. I can't say what is happening in all other States, but as far as Andhra Pradesh is concerned, in the year 1992-93, 22 handloom development centres had been sanctioned, but what are the grants and loans given to them? After a personal representation by me they have disbursed at the rate of rupees four lakhs to each of these 22 societies and some other things—a small amount to each of dying units. They said that the grant portion is 11 lakhs and the loan portion is 16 lakhs. Did they give the full amount to any particular society? Let them say, I am here to hear the Development Commissioner of Handlooms, when the scheme has been sanctioned, when the societies were selected and what amounts have been given to them. How is it possible for these handloom development centres to provide employment to 250 looms? When can they provide employment to 1000 people. According to the norms of the NABARD there shall be a working capital of 16 lakhs, then only it would be possible to provide employment to the handloom weavers in the society to which this handloom development centre has been sanctioned. As there is no time, I am not going into the details of all these things.

Madam, the main drawback of the handloom industry is its total dependence upon the centarilsed mills. They use up their yarn, spun in their spinning sections, in the weaving sections or conversion into cloth, but the handloom weavers are obliged to pay 30—35 per cent extra over the actual price of the yarn in the form of reeling, bundling, baling, transport, bank charges insurance interest profits of mills and middlemen. Apart from that, there are taxes also which have been levied by the Centre, State Governments and also local taxes like octroi. This fact has been established by several committees appointed by the Government of India as also by the State Government's. When this was represented to Pt. Jawaharlal Nehru who was the President of the National Planning Committee, constituted in the year 1949, immediately after the Independence-Sarvashri Vallabhbhai Patel and Mr. Ranga were also its members—they recommended that all raw materials used by and the products produced by handlooms shall be free from fiscal levies.

Has that been accepted by the Government of India? No. Sir, in the year 1985, Shri V. P. Singh, the then Commerce Minister, declared 1985 as a year of handlooms. He addressed letters to all the Chief Ministers of States and Union Territories requesting them to abolish sales tax on all raw materials used by handloom weavers. Kerala Government was the only Government which accepted the suggestions of Mr. V. P. Singh to some extent. Other States have raised questions as to why the Centre should not abolish the excise duty and why not the Central Government abolish the Central sales tax before

asking the State Governments to abolish all the sales tax on hank yarn. There was no response. Even today there is no response from the Government of India.

I saw the Prime Minister on 22nd February, 1993. I requested him to see that excise duties on dyes and chemicals were reduced to some extent to help the handloom weavers. Mr. Ardhanareeswaran was the then Secretary of the Ministry of Textiles. The Prime Minister asked Mr. Ardhanareeswaran to try to convince the Finance Ministry and see that dyes and chemicals used by the handloom industry were given some sort of reduction in duties, though not all, and then, on my pressure an inter Ministerial group was also appointed.

That group recommended that dyes and chemicals shall be made available to handlooms at reduced rates of excise duty. There was no response Either the Finance Ministry did not reply or the Ministry of Textiles were not able to convince the Finance Ministry in this regard. Therefore, Madam, even though the Ministry of Textiles have taken certain steps to bring down the price of yarn, were they successful?

In the first instance, they said, they are allowing the mills to import ten lakh bales in two instalments free of import duty. They also permitted the mills to import 30,000 metric tonnes of viscose staple fibre for the purpose of blending it with cotton to augment the production of blended yarn. Immediately I asked the Government: what was the national loss of revenue by permitting the mills to import 10 lakh bales of cotton and also 30,000 metric tonnes of viscose staple fibre. At least, the Government might have asked the mills concerned to supply the yarn produced out of the 10 lakh bales of cotton and 30,000 matric tonnes of viscose staple fibre. But, there was no reply. Even today, there is no reply. There was a sudden increase in prices in November 1993. The increase in yarn prices was more than 50 percent in January 1994. I would like to ask the Ministry of Textiles what prompted them when the weavers were suffering not only for want of yarn but also increase in prices of yarn, to fix an export ceiling of 100 million kgs of yarn? All right. They have fixed 100 million kgs as the ceiling for exports. But, how much have they allowed? Two hundred and nineteen million kgs. of yarn! The ceiling fixed was only 100 million kgs and the actual yarn exported was 219 million Kgs. Then, according to the hank yarn obligation orders, the producers of yarn including the exporters who are also producers of yarn, should spin hank yarn to the extent of 50 per cent of their marketable out put.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Kotaiahji, please ask the question.

SHRI PRAGADA KOTAIAH: I am coming to that. I will not take much of your time.

Then I presented a memorandum to the Prime Minister, "Sir, there are three categories of exporters who did not supply even one kg. of hank yarn. So, sir you direct the exporters to supply hank yarn to the extent of 50 per cent of yarn exported by them." On the 20th March the Ministry of Textiles issued a notification not exempting export of cotton yarn from the hank yarn obligation orders. Is this the way that the Government should work in the interest of the handloom weavers? After I presented the memorandum to the Prime Minister, on 16-3-95 I had discussed the matter with the Minister, where the Handloom Development Commissioner was also present on the 17th, and they said, "We will find out." But, on the 20th they issued a notification exempting exports of yarn from the hank yarn obligation orders. When you are asking that there should be no export of rice because the people are starving,

country cannot afford to export rice Madam, handloom weavers are the poor people having no organisations to shout slogans and make noise. So, the Government is doing what they likes. The Prime Minister was telling us that the needs of the poor would be met on a priority basis. Is this the way to meet the needs of the poor people on a priority basis? When we are asking the Government and the Ministry of Textiles also accepted, that instead of exporting yarn, the value added products should be exported to make more money, to earn more foreign exchange, which is advantageous not only to the Government but also to the exporters. But, what has been done? We are not asking for a 'paise' from the Government. But, what we are suggesting is that the exporters to whatever category they may belong, they should import cotton to produce yarn and export. There may be two categories or three categories or whatever they are, they shall not use Indian cotton as long as the position of cotton availability is tight. Due to the liberalised industrial policy more than 100 mills, spinning mills, have come into being after 1992-93. They should also be directed to use imported cotton or man-made fibres for conversion into yarn. The Government is making every effort for improving the availability of man-made yarn for which there has been a reduced excise duty. There has been a reduced excise duty on man-made fibres. Therefore, I am asking the Minister of Textiles that if he is really sincere about the interests of the handloom workers, he should withdraw this notification of 20th March exempting exports of yarn from bank yarn obligation.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Kotaiah, I feel your live intention is to help the handloom weavers and that is why you have been permitted to raise this Calling Attention. I think your case would be more strengthened if you allow other Members also to support you. So, please allow them to speak.

SHRI PRAGADA KOTAIAH: I am concluding, Madam. So, I am making an appeal to the Prime Minister to set apart one crore of rupees for the introduction of domestic spinning units with 12 and 24 spindles. When it will be possible for the handloom weavers to have domestic units for 24 spindles? I would like to ask the Department also to go to Gandhigram in Tamil Nadu and see how the domestic spinning units are working for the betterment of the handloom weavers. Therefore, Madam, I make an appeal to the Prime Minister to find a permanent solution as long as we depend upon the centralised spinning mills. We did get yarn. Even in 1945. When there was scarcity of yarn, I approached Gandhiji. Then he sent a post card and asked me, "you spin your own yarn." That is what Gandhiji suggested in 1945. But we made a mistake in organising cooperative spinning mills which are of no help to us. Therefore, now I appeal to the Minister to set apart one crore of rupees for popularising the domestic spinning units in the rural parts of the country. To start with, you give us one crore of rupees. (*Time-bell rings*) Madam, one sentencee and I will complete because several people think that the handloom industry has no future, but Madam this is the Fact Finding Committee Report of 1941. The future is not there for the composite weaving mills because of competition from the powerlooms with lower low cost of production. It has been mentioned in the Annual Report by the Ministry of Textiles. This is the third finding of the Fact Finding Committee. One sentence I will read out and I will conclude my speech. "Powerloom competition:—As already stated, a more serious rival to the handloom industry than mills has arisen in the small-scale powerloom factories. This rival combines in itself, owing to its medium-scale production, the advantages of both mills and handlooms. It can utilize cheap electrical power and avail itself of the modern appliances in

(Shri Pragada Kotaiah)

weavng. The competition of power-looms is a growing phenmenon; about 15) years ago the handlooms and nothing to fear from them. Power looms are not subject to any irksome restrictions such as the Factories Act or special taxes. As such, they are a source of competition in important lines to the mills as well. The cost of production in powerlooms is comparatively lower owing to small overhead charges and economies of mechanical production. Thus the contest has now become a three-cornered one." The Committee also said, that if a mill does not earn profit it will close down but the handloom with its meagre wages continues to work because. unfortunately, handloom weavers have no other alternative open to them. That is the present miserable condition of the handloom weavers. I would say, for the sake of the Minister I will read out what the Fact-Finding Committee Report lastly has said.

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is from the Report, isn't it?

SHRI PRAGADA KOTAIAH: "The handloom industry has survived and will survive. The question is whether it will survive as a relic of primitive economy, a symbol of sweating and low standard of living. Or will it survive and grow strong as the corner-stone of a healthy, decentralized modern economy which will maintain in freedom millions of families on a reasonable standard of comfort, while ensuring to the population at large a steady supply of clothing even in times of possible insecurity? The answer to this question will depend on the wisdom and forethought which the present generation of India will be able to bestow on this very important problem."

I appeal to the Prime Minister to consider the present situation and help the handloom industry.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri Viduthalai Virumbi. Just only questions because the ground has been prepared by him. He has woven the whole thing. You have just to print it. Put the questions, please.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Madam Deputy Chairman, first of all, this particular Calling-Attention Motion has been tabled in view of the crisis in the handloom industry. But the statement says that there is no crisis in the handloom industry. They are denying the very existence of a crisis because of which this particular Calling-Attention Motion has been brought before this House.

On page 2 of the statement, in paragraph 4, the Minister says: "Hon. Members have been expressing concern from time to time regarding availability of hank yarn at reasonable prices". Madam, the problem is still lingering on. They have produced some statistics. What I feel is that it would take two-three days for us to verify whether the statistics are correct or not. They are giving such a type of statistics only to see that we do not raise any questions here.

Madam, what is the real situation as far as yarn is concerned; hank yarn and cone yarn? This has already been explained by Shri Kotaiah. Some people have lost their lives. The people who are engaged in the handloom sector have lost their lives in Andhra Pradesh due to poverty. In Tamil Nadu, in Tirupur, the baniar industry is completely crippled; it is paralysed. Not only that.

When we raise the question about hank yarn here, the Government says that everything is all right. But in reality, it is not so. What do you see when you go through the figures in respect of production as well as export of yarn? Take, for example, hank

yarn. The target for export for the period 1991-92, 1993-94 was Rs. 3,095 crores. But the actual achievement in yarn export was Rs. 3,764 crores. Therefore, they have exceeded the target by Rs. 669 crores. There is a restriction here. They should not export yarn upto 60 counts. This restriction was not adhered to by the exporters. Unfortunately, there was no monitoring done by the Government to ensure that the exports are made as per the norms prescribed by the Government. I would like to know from the hon. Minister whether it is a fact that there is a restriction that up to 60 counts, yarn should not be exported. Is there any such restriction? If there is such a restriction, what has been done by the Government to see that this restriction is adhered to, to see that it is implemented properly? I would like to know that.

The Government says that there is no scarcity of hank yarn, that people make a hue and cry. Madam, everybody knows that there is scarcity, I myself met the Minister at his residence. He said that the subsidy on hank yarn could be increased by a further 5 per cent. This is what he said.

The yarn production in the mill sector is 1,272 million kg. Out of this, 50 per cent has to be given to the handloom sector. This is mandatory we can say. It is an obligation cast on the mills to see that 50 per cent of this 1,272 million kg. is given to the handloom sector. But what has actually been given? Only 366 million kg. What about the balance? Has action been taken against the erring mill-owners. Nobody has taken any action. This is very clear.

Another important thing is, we have to protect the workers. Workers are workers, whether they are in the handloom sector or in the powerloom sector or in the mill sector. We have to protect the workers in all these sector. I do not have any *bias* in favour of any particular sector. Madam, I would like to point out here that on hank yarn, there is no excise duty; on cone yarn, there is excise duty. Automatically, therefore, there is a difference in the price between the two. What is happening is that the people who are having hank yarn are converting it into cone yarn. With some arrangement within the house or in a small factory, they are doing it. The hank yarn is being converted into cone yarn. To stop this malpractice, I can say, to the best of my knowledge, that the Government has not taken any action. Therefore, the scarcity is still continuing. On the other hand, you are giving some statistics compiled by the local officials. This is not the market situation.

In the case of cone yarn also, it is exported. When they export, they earn some profit. This, automatically, results in the scarcity of cone yarn. Because of that they had sent out more than 60,000 workers from the factories in Tiruppur. Still they did not come back. Nobody is bothered about it. That is the situation.

Then, cone yarn is in scarcity, hank yarn is in scarcity, prices have not doubled but quadrupled. They should not go through these statistics. What I ask is, let the Minister go through the newspapers. From three years before you take some four or five newspapers—whichever papers you select, it is left to you—of four or five weeks and then find out the market price prevailing and then see what is the market price prevailing now. Then you will find out what you have given. You have not given the prices prevailing three years before and what the current prices are. You have not given these in your statement. Why has it not been done? Because, had you

given these prices, then, automatically we will know that our entire statement is untrue. That is why you have not given them. Only you have said what arrangements you have made to give some hank yarn, 20 million kg. or 10 million kg. You have given all these paragraph by paragraph, but you have not given the exact prices which were prevailing three years before and which are prevailing now.

SHR G. VENKAT SWAMY: I will give you now.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI. Thank you very much. I think the hon. Minister will honour his commitment. Then we will find out the prices... (*Time-bell rings*)...

Madam, therefore, as far as hank yarn is concerned, firstly, it is not available in the market. If he wants any proof, he can see that the entire handloom sector in Tamil Nadu, particularly around Karur, is completely, paralyzed. Cone yarn is not available. The prices have quadrupled scarcity is there, price increase is there, and the entire industry is paralyzed . But no proper action is taken. You have taken action, but no proper action has been taken to solve the crisis. I want to know what you are going to do. What I feel is, he has not given the true picture in this statement. Thank you, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. S Madhavan... Not here. Shri Gurudas Das Gupta. Now, only questions, please.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA Madam, I feel that this is not a problem of the handloom sector only. This is a textile crisis, this is a national crisis and the hon. Minister's statement is an absolutely misleading statement. He holds out a lollipop of assurances, without caring or without ensuring whether his assurances are fulfilled or not.

Therefore, the question is not whether millions of handloom weavers are starving or not. That, of course, is true. But the main point is this, that India is a country where not only the largest number of illiterate people live but it is also a country where people are becoming ill—clad every day. The per capita consumption of cloth has gone down in the country. It was 13 metres per head, now it is less than 10 metres per head. Therefore, the essential point is, cloth production has gone down, people are becoming ill-clad and, at the expense of the national interests the Minister is pampering the exporters to capture foreign markets and earn foreign exchange. Therefor, this policy is anti-national and this policy is against the interests of the nation as a whole. It cannot be said that it is against the weavers only.

What are the statistics? Will the Minister take the trouble to answer whether the per capita consumption of cloth has gone down or not, whether there has been an abnormal increase in the prices of textile goods all over the country or not, whether it is true that the price of the yarn which is being supplied to handlooms is at least 25 per cent above the ex mill rates or not, whether he will agree that there has been a sharp decline in the supply of yarn to the handlooms, whether he will agree that it is because of the short supply and high prices and export craze and craze of the Government to pamper high-value textile products that the present situation has been created? This is a part of the textile policy. The textile policy is precious, and we can only see the effects of the pernicious textile policy in the mass pauperisation, in the mass under-employment and in the mass poverty of the handloom weavers who cosntitute a significant part of the working population in the countryside living

1 P.M.

below the poverty-line. This is the accusation.

Madam, a number of new mills have been set up to produce yarn. The Government has given them tax concessions. The Government has allowed them to import high-valued machinery. All sort of concessions have been given to them. These mills are producing yarn and enjoying the privilege of the Government, but they are just exporting the product. Therefore, at the cost of the national exchequer, not only are we depriving the weavers but also, we are creating a situation where the per-capita availability of cloth and the per-capita use of cloth go down. Therefore, the textile policy is wrong, pernicious and against the people.

Madam, not only are the new mills indulging in export, but they are also violating the Government Order so far as the mandatory Order for supply of yarn to handlooms is concerned. There is nobody to enforce the law in the country. The Government has abdicated its responsibility. The Textile Ministry is there only to sign agreements and to see that the agreements are never implemnted. Mr. Venkat Swamy is presiding over the liquidation of the textile industry, and he can be held responsible for aggravating of the problems of the textile industry in the country, not only affecting the handloom sector but also affecting the country as a whole, the population of the country as a whole.

Madam, supply of yarn has gone down because it is being exported and because a large number of mills have been closed down. Not less than 110 mills have been closed down. A large number of textile mills are operating just nominally. They are also being closed down. Two lakh workers have been retrenched. According to my calculation 50 per cent of the weavers are under-employed. They do not have any job because there is no supply. They do not have any job, and, therefore, there is no wage. They do not have any wage, and, therefore, they are living below the povertyline and they are starving. It is on the denial to the common people and their starvation that yuo are building an artificial prosperity of export. You have built your craze for catering to the needs of high-income group in the country High-valued textiles are being produced to cater to the needs of the high-income group. Instead of marching towards self-reliance, the textile industry is creating a situation where the country is marching into the lap of the Reliance Company.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Gurudasji, are we discussing the entire textile policy?

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Yes.

THE DEPUTY CHAIRMAN: No, we are not.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Yes, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am so sorry. We are not discussing the entire textile policy.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Handloom is being denied because Reliance is being pampered. That is my contention.

THE DEPUTY CHAIRMAN: No, no. I have no problem if you discuss anything, but not now.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: I want to know from him why mills producing high-valued cloth are being pampered at the cost of the interests of handlooms. That is my essential point. The Textile Ministry is not only denying yarn to handlooms but it is also denying cheap

cloth to the common people. At the cost of the common people and handloom weavers, we are exporting, and super profit is being made and manipulated by mills producing high-valued cloth in the country.

Therefore, my first question will be whether you will ensure that there will be a serious curtailment of export of yarn. I demand curtailment of the export of yarn. I demand the mandatory order for the supply of yarn to the handloom is really enforced. Those who violate it should be brought to justice. I demand let the Government say that they would create a situation whereby additional concessions would be given to the handloom weavers in the form of withdrawal of taxes, in the form of subsidy, in the form of cheap bank loan, in the form of purchase, in the form of Government orders. The handloom weaver has to be protected and there has to be a specific Government decision. We are not ready to listen to what the Government intends to do; we want to know what the Government is actually trying to do.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Gurudas Das Gupta, just one second, please. If you do not help me in running this House, then you would not help your colleague. Please put questions. Mr. Pragada Kotaiah has a very specific Calling Attention Motion about handloom. I would be happy if you discuss the entire textile policy or the industrial policy. I have no problem. But if you please put pointed questions, then I assure you that you will get pointed answers. But if you are going to discuss it, then he will definitely say it is beyond his perview. So, you would not get answer and you would say the Minister is not answering.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: I will not give any scope to the Minister to get away. That is not the point.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I will give him the scope to get away because it will be beyond his Ministry.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam Chairperson, it is an interlinked question. My charge against the Government is that the handloom sector is being discriminated against to favour the big ,high-valued, textile mills of the country.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Do not repeat. It would not go on record.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: I am not repeating .I would like him to tell me whether he is ready to put a curb on exports; I would ask him to tell us if he is ready to organise a package for the handloom sector in the form of further subsidy, give them bank loans and a particular order from the Government. Thirdly, considering the serious privation of the handloom weavers and workers; I would like to know whether the Government will ensure that some social security measures will be taken at least for a temporary period to give relief to them.

THE DEPUTY CHAIRMAN: That is much better and he can answer.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: He will not answer because he will need the Cabinet's approval for the answers.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Jibon Roy. Please put questions to get an answer.

SHRI JIBON ROY (West Bengal): Madam, I am incapable of making a long speech.

I thank the hon. Member and my elderly brother for raising this issue in the House. It is a most important issue and I share his concern, because I am associated with the working class movement. I know the problem of weavers to an extent, though

I do not understand the problem in detail. But, one thing I wish to mention here is that you may expect a golden pot, but I cannot be made of stone. You support the Government which has adopted a policy very recently which is contrary to a Welfare State, a policy of the survival of the fittest. Every year perpetually the Government is raising the investment ceiling of the small-scale industries and the big industries are entering into the small-scale areas.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We are not on small-scale. We are still on the handloom.

SHRI JIBON ROY: Handloom is in the small-scale, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please confine yourself to the handloom.

SHRI JIBON ROY: What is the status of the powerloom?

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am sorry. I am going to be very strict. I will not allow you to speak if you do not stick to the subject under discussion. There are many other hon. Members who know the subject. I have Members here who have spent their lives in this. I would like them to put questions to the Minister on the handloom sector. No discussion other than that.

SHRI JIBON ROY: I am very much on the point, Madam. But, what is the main problem of the handloom industry? The main problem is that the mill sectors are closing their mills and are investing their money in powerlooms. A competition is going on between powerlooms and handlooms. And investment on powerlooms is taking place because of the change of the policy of the Government. I have a figure with me which shows that the per capita productivity in the handloom sector between 1989 and 1990 and 1992 and 1993 has gone up by only five per cent. The productivity in the powerloom sector has gone up by 15 per cent. If the workers' strength in the handloom sector is ten million, as it is reported in a report of the Government, the per capita production comes to 442 metres per year. The per capita production in the handloom sector comes to 2,971 metres per year. This is the competition between the handloom sector and the powerloom sector. In the powerloom sector, the industry does not pay wages to the workers. Sometimes they pay Rs. 600 or Rs. 700 or Rs. 800 per worker. Therefore, an uneven competition is going between these two sectors. The then Janata Dal Government had decided that after 1990 there would be no expansion of the powerloom sector. But the investment in the powerloom sector is going up every day. Therefore, this restriction has to be imposed.

Secondly, there has been some commitment given by the Government to the handloom weavers to produce hank yarn and every year at least 50 per cent of the product would be marketable. Even that commitment also has not been fulfilled. According to the figures given by the Ministry of Textiles in the House, in 1993-94, mills should have produced about 650 million kgs. of hank yarn but they have produced only 372 million kgs. of hank yarn. Out of 372 million kgs. of hank yarn, about 40 per cent has been siphoned off by the powerloom sector. What steps have you taken? According to the explained position Handloom Sector require around 600 million Kgs of hank yarn every year. But that is not being produced. Apart from this, the export of hank yarn is also going up. According to the figures available, in 1989-90, 40 million kgs. of hank yarn was exported. In 1992, they have exported 145 million kgs. of hank yarn. In 1993-94, they have exported 200 million kgs. of hank yarn. How could you expect the handloom sector to survive this offensive?

SHRI G. VENKAT SWAMY: We did not export any hank yarn. You should know the difference between hank yarn and cotton yarn.

SHRI JIBON ROY: You have exported both.

SHRI PRAGADA KOTAIAH: Whether you have exported hank yarn, cotton yarn or whatever it may be, automatically the production of hank yarn is going down. You have not said about that. Why?...(*Interruptions*)...

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: They are not supplying the hank yarn to the handloom sector. That is the point. You must understand that it is in short supply...(*Interruptions*)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Kotaiahji, the Chair is this side.

SHRI PRAGADA KOTAIAH: I would request the Prime Minister...(*Interruptions*)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am not allowing anybody. Please sit down...(*Interruptions*)...Kotaiahji, please sit down. The Minister is competent enough to answer all your queries.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Let us see.

SHRI PRAGADA KOTAIAH: Let the Minister answer all my queries in English only. We will not be able to follow his reply in Urdu.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The translation system is working.

SHRI PRAGADA KOTAIAH: This subject is more of a technical nature Therefore, ask him to reply only in English so that I may be able to know what he is telling us.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Kotaiah, just now, the Minister is not speaking but Mr. Jibon Roy is speaking. He is speaking in English. I think when the Minister spoke, the translation was on. So, put on your head phone. If your head phone is not working, please let me know so that I will see to it that you get proper translation. Secondly, the statement of the Minister was only in English, not in any other language, not even in Hindi. So, please read it. If you had any problem at that time, you should have told me. Now, it is too late. He has already spoken.

SHRI PRAGADA KOTAIAH: He did not mention all the issues in his statement. We have mentioned only with regard to yarn. Let him answer straight.

THE DEPUTY CHAIRMAN: If you do not interrupt and let me finish the discussion, I assure you that he will answer. If you don not allow him, if you do not give him time to answer, then I do not give you any assurance.

Mr. Jibon Roy, we are not discussing the policy in detail. Please put your questions.

SHRI JIBON ROY: Madam, I am very much discussing handloom I am not going beyond that.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Questions please.

SHRI JIBON ROY: According to the 1985 Textile Policy, 22 handloom items were reserved for the handloom sector. And the textile mill owners went to the Supreme Court. There was a stay. The Supreme Court vacated the stay. But still, the Textile Ministry is not enforcing that 1985 stipulation. Therefore, it has got to be enforced.

Besides that, the Government should take steps for diversification in the handloom sector. The handloom sector can produce many things. The export potential is increasing. The

export of handloom material is increasing every year. For diversification also, technical help and finance are necessary.

The second thing is marketing. So far as marketing is concerned, there also, the handloom sector is entirely at the mercy of the mill sector and the textile sector and co-operatives Of course, some co-operatives are helping. But there is a complaint that many co-operatives do not pay up the money to the weavers regularly and they usurp the funds. It happened in the case of the janata cloth also. The wage supposed to be paid to the handloom weavers had not been paid. Marketing is an important aspect. The Government should see that in the matter of marketing also sufficient support is given. There should be some balance in the imposition of excise also. For some time now, since the 1991 Budget, there has been an obsession in favour of synthetic yarn. As a matter of fact, totally, the price of cotton yarn goes up in comparison to the price of synthetic yarn. Hank yarn also suffers out of this.

These are the main submissions I have to make to the hon. Textile Minister. I hope he will respond to these points.

Thank you, Madam.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : माननीय उपसभापति जी, मैं मंत्री जी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि जो हथकरघा उद्योग है उसमें कोई भी संकट नहीं है। मंत्री जी ने जो विस्तार से अपना वक्तव्य दिया है उसी से यह बात साफ हो जाती है। यह सही है कि हमारे देश में कृषि के काम में जितने लोग लगे हुए हैं उसके बाद दूसरे नम्बर पर गांव के और कस्बों के अधिकतर गरीब लोग इसी काम में लगे हुए हैं। मैंने मंत्री जी के वक्तव्य को बहुत ही ध्यान से पढ़ा और सुना। मुझे केवल 5–6 स्पष्टीकरण पूछने हैं। एक तो यह कि आबिद हुसैन कमेटी थी जिसका सुझाव था कि सूत को सस्ते दामों में रियायती दर में बुनकर को उपलब्ध कराना चाहिए। मेरा प्रश्न यह है कि बुनकरों को सस्ती कीमतों पर, रियायती दरों पर सूत उपलब्ध कराने के लिए पिछले दो वर्ष के अंदर सरकार की ओर से क्या कदम उठाए गए हैं क्योंकि माननीय सदस्यों ने भी इसकी ओर ध्यान आकर्षित किया है कि आज भी रियायती दरों पर सूत बुनकरों को नहीं मिलता है इसलिए गुरूदास दासजी गुप्ता ने भी इस मांग को रखा है कि रियायती दरों पर इनको सूत उपलब्ध कराना चाहिए।

फरवरी, 1993 में एक अखिल भारतीय बुनकर सम्मेलन दिल्ली में हुआ था। प्रधानमंत्री ने उसको सम्बोधित किया था और वर्तमान मंत्री श्री वेंकट स्वामी जी ने भी उसको सम्बोधित किया था। तब प्रधान मंत्री जी ने और इस विभाग के मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कुछ आश्वासन भी दिए थे, कुछ घोषणाएं भी की थीं। यह बात है फरवरी, 1994 की, तो एक तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जो आश्वासन और घोषनायें आप लोगों ने बुनकरों के अखिल भारतीय सम्मेलन में की थीं वे आज तक कार्यान्वित नहीं की गई हैं, तो उनको कार्यान्वित करने में क्या दिक्कत है? एक हैंडलूम्ज (रिजर्वेशन आफ आर्टिकल्ज फार प्रोडक्शन) एक्ट, 1985 है। संसद् ने जब इसको पारित किया उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में इसकी वैद्यता को चुनौती दी गई। 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह कानून वैद्य है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है अभी तक अर्थात् आज की तारीख तक भी यह कानून अच्छे तरीके से, प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं हो रहा है, उसका इम्पलीमेंटेशन नहीं हो रहा है और अभी मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में इस बात को कहा भी है कि इसके सिलसिले में कोई एक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है, जिसकी पहली बैठक 20 अप्रैल, 1995 को हुई है। एक तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो सन् 1985 का कानून है इसको इम्लीमेंट करने में सरकार के आगे क्या-क्या दिक्कत है, जबकि सुप्रीम कोर्ट से सरकार के पक्ष में और इस कानून के पक्ष में

फैसला भी हो गया है? दूसरा यह जो एडवाइजरी कमेटी है इसका टर्म्स आफ् रेफ्रेंस क्या है और इसके कौन-कौन से सदस्य हैं, इसको बताने की कृपा करेंगे?

एक अच्छा काम आप शुरू करने जा रहे हैं कि सारे देश भर में जो 20 मोबाइल वैन हैं इनको आप चालू कर रहे हैं, तो मैं आशा करता हूं कि आपने यह जो शुरूआत किया है भविष्य में इनकी संख्या में आप धीरे-धीरे निश्चित रूप में वृद्धि करते जायेंगे। साथ ही यह जो इस कारोबार में या इस काम में जो लोग लगे हुए हैं वे बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं, चाहे गांवों के रहने वाले हों, चाहे कस्बों के रहने वाले हों, आन्ध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में और सारे परिवार के लोग इसमें लगे रहते हैं, पुरूष, स्त्री और उनके बच्चे इसमें लगे रहते है लेकिन इसके बाद भी उनकी जिन्दगी बदहाली में व्यतीत होती है, तो मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस काम में जो लोग लगे हुए हैं उनके आर्थिक स्तर को सुधारने के लिए, उनको आवास की सुविधा हो, उनके बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधा हो, बीमार पड़ जाए तो उनकी चिकित्सा के संबंध में भी सरकार द्वारा कुछ सहायता की जाएगी?

इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप देने की कृपा करें।

SHRIMATI MIRA DAS (Orissa): Thank you, Madam. I do not entirely agree with the allegation made by Mr. Gurudas Das Gupta that the Minister is presiding over the liquidation of textile industry but I agree to the extent that the Ministry should have sincerely worked for the development of textile industry, it would have created more number of jobs in the rural areas Madam, I am not going into the details. The other Members have already mentioned the points. I am only concentrating on the achievements made by the Ministry after the present Minister has taken over the charge of the Ministry of Textiles. During 1993-94, the employment generation in the handloom sector, which is directly related to actual production, has been estimated at 124.82 lakh persons. I want to know from the Minister what is actual achievement is? The Minister has just now told us that he is working for the development of the poorest of the poor and wants to bring them above the poverty line. It is a good but it lacks sincerity So far as the schemes which have been formulated by the Government are concerned, they have not yet been implemented What will the Minister do to bring the people, who are below the poverty line to bring above the poverty line? Madam, the National Council for Cooperative Training has been conducting training programmes since 1979-80. For the development of all the cadres in the handloom sector. But it is suffering for lack of funds in the same way as other cooperatives are suffering.

Madam, I would like to know this from the hon. Minister. What has happened to the Abid Hussain Committee report? Has it been put into cold storage or is it still being considered? The Government announced some schemes for handloom weavers under various rural development programmes. Madam, as you know, the other day, the Prime Minister was mentioning about rural development programmes. All Members of Parliament know what really is happening in rural areas under the rural development programmes and rural employment programmes. Madam, since 1993 nothing substantial has happened in the Textile sector In 1991-92, the Integrated Handloom Village Development Scheme was introduced to help the handloom weavers in villages. But what has happened to this Scheme? How is it helping the handloom weavers in the villages. I know the Minister is very sincere. But what do we do if he is chained up everywhere? He

He has no freedom to do anything because of the powerloom giants. Mr. Jibon Roy has already mentioned that 26 items which were independently reserved for the handloom sector have not been introduced so far. I don't know under whose pressure the Ministry is not able to do it. I would like to know from the Minister whether he is going to implement this scheme or not. In the light of the Supreme Court's decision the Government should come forward to implement this scheme; otherwise, it is not going to create any employment facilities in the rural areas. Madam, as you know, it is the only rural-based industry which can give employment to millions of rural people. Thank you.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now we have only a few minutes before the lunch hour.

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now what can we do? This is a very important matter and the Minister is not free tomorrow. We don't want to leave it for the evening because the whole discussion is in the process. We have to discuss the Budget (Railways) also. The name of Mr. Ram Ratan Ram is there and four more names are there who want to put questions. Everybody wants to put questions. Then there will be the reply of the Minister. After the lunch hour we will have one hour to finish this Calling Attention Motion. The Members would take half-an-hour to put their questions and then the Minister would answer. Then we will take up the Budget (Railways). We will adjourn the House for lunch now, if the House so agrees.

SOME HON. MEMBERS: Yes.

THE DEPUTY CHAIRMAN: If you want to sit a little late we can sit late because we have to finish six hour discussion on the Railways.

The House is adjourned for lunch.

The House then adjourned for lunch at twenty nine minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-one minutes past two of the clock,

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL) *in the Chair*

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल) : श्री राम रतन राम। जरा समय का ध्यान रखें क्योंकि ध्यानाकर्षण-प्रस्त व डेढ़ बजे तक खतम करना था कुछ स्थिल-ओवर हो गया है। जल्दी हो जाए तो अच्छा है।

श्री राम रतन राम (उत्तर प्रदेश) : सर, मैं बहुत कम समय लूंगा।

उपसभाध्यक्ष महोदय अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान दिलाने हेतु "हथकरघा उद्योग में गहरे संकट जिसकी वजह से हथकरघा बुनकर अल्प-रोजगार और बेरोजगार हो रहे हैं और भुखमरी के शिकार हो रहे हैं" पर यह प्रस्ताव लाया गया है। माननीय मंत्री महोदय ने इस विषय पर अपना एक वक्तव्य देकर उक्त धारणा का खण्डन किया है। उनका कहना है कि वर्ष 1991-92 में 87.96 लाख व्यक्ति कार्यरत थे जबकि 1993-94 में 116.20 लाख व्यक्ति कार्यरत थे। उन्होंने यह भी कहा कि हथकरघा उद्योग में 1991-92 में उत्पादन 4130 वर्ग मिलियन मीटर था, जो 1993-94 में बढ़कर 5851 वर्ग मिलियन मीटर हो गया। माननीय मंत्री जी ने जबसे कार्यभार संभाला है तब से कपड़े के उत्पादन में तो वृद्धि हुई है, निर्यात बढ़ा है और सबसे खुशी की बात है कि माननीय मंत्री जी के पद व गरिमा में भी वृद्धि हुई है जिसके लिए हमारे मंत्री जी बधाई के

पात्र हैं, पर यह देखना जरूरी है कि ऐसे क्या कारण हैं जिससे हथकरघा बुनकरों को कष्ट हो रहा है।

महोदय, इस समय कपड़े का उत्पादन हथकरघा पावरलूम व मिल के माध्यम से हो रहा है। मिल आर्गेनाइज्ड सेक्टर हैं। मिल चले या न चले, मजदूरों को उनका वेतन बोनस मिलता रहता है, लेकिन वह लाभ हथकरघा उद्योग में लगे लोगों को नहीं है। इसका लाभ हथकरघा उद्योग में लगे व्यक्तियों को नहीं मिलता है। हथकरघा उद्योग कृषि की भांति घर घर में फैला हुआ है। उसको सूत मिलना चाहिए नियमित रूप से, तभी वह काम कर सकेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सूती मिलों से यह अपेक्षा की गई है कि वह 50 प्रतिशत तक हैंकयार्न बनाएंगे, जिससे कि हथकरघा उद्योग बराबर चलता रहे, पर ऐसा नहीं हो रहा है। अधिकांश मिलें 40 प्रतिशत तक हैंकयार्न का उत्पादन कर रही हैं, जिसके कारण हथकरघा उद्योग के लिए जो व्यक्ति लगे हुए हैं, वह साल में केवल 275 दिन काम करते हैं और बाकी दिन बेकार रहते हैं। मंत्री महोदय ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वे खाली दिनों में हथकरघा उद्योग में लगे व्यक्तियों के लिए क्या करने जा रहे हैं या जो मिलें हैंकयार्न का उत्पादन निर्धारित मात्रा में नहीं कर रही हैं, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही वे करने जा रहे हैं?

मंत्री महोदय ने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि मिल पावरलूम ने हैंडलूम में लगे व्यक्तियों की मासिक आय में क्या अन्तर है क्या उस अंतर को कम किया जा सकता है? हैंडलूम को पावरलूम से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। पावरलूम में कपड़े की कॉस्ट कम आती है और उससे हैंडलूम में व्यवस्था बिगड़ी है, हैंडलूम रिजर्वेशन आर्टिकल 1985 की पालिसी के अंतर्गत जो एक्ट बनाया गया था उसमें 22 आइटम हैंडलूम के लिए सबसे पहले छोड़ी गई थीं, लेकिन पावरलूम के आ जाने से हैंडलूम की व्यवस्था चरमरा गई है।

हथकरघा उद्योग में लगे लोगों की आर्थिक दशा खराब है, एक परिवार जिसमें पांच-छः लोग रहते हैं, सभी हथकरघा में लगे रहते हैं और एक लूम पर अधिक से अधिक 10–12 रुपए की आमदनी होती है, हथकरघा उद्योग में जो लोग सिल्कन साड़ी बनाते हैं, उनकी अवस्था तो कुछ ठीक है लेकिन जो लोग सस्ता कपड़ा बनाते हैं उनकी हालत ठीक नहीं है, हथकरघा उद्योग में 1987 की सैंसस के अनुसार जो उन्होंने सेज बताई थी, मासिक आय बताई थी उसमें 14.32 लाख बुनकरों को 501 रुपए से अधिक की आमदनी होती थी, 13.34 लाख बुनकरों की आय 201 रुपए से 500 रुपए तक थी, 2.04 लाख लोगों की आय 200 रुपए से कम की थी।

हैंकयार्न का उत्पादन रूई की सप्लाई पर निर्भर करता है लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि 1994 में गवनमेंट ने डिसीजन लिया कि 5 लाख कॉटन बेल का सितम्बर तक एक्सपोर्ट किया जाएगा, इधर उन्होंने जनता क्लाथ का उत्पादन बंद कर दिया, जनता क्लाथ का उत्पादन बंद होने से असम में गहरा संकट छाया हुआ है। असम में 41 परसेंट हैंडलूम जनता क्लाथ के उत्पादन में लगे हुए हैं, जिसमें करीब 20,000 विधवाएं भी शामिल हैं जो हैंडलूम के कारोबार से अपना जीवन यापन करती हैं, जिस कपड़े का उत्पादन हुआ है, वह सेल नहीं हो रहा है वह सारा स्टाक में पड़ा हुआ है जिससे जो जनता क्लाथ के उत्पादन में लगे हुए लोग हैं, वे बेकारी की स्थिति में हैं वे भुखमरी के कगार पर हैं, क्या मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर गया है कि जनता क्लाथ के उत्पादन में जो विधवाएं लगी है, जो गरीब लोग लगे हुए हैं, लाखों लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं जो भुखमरी के कगार पर हैं, क्या उनके लिए कोई रास्ता मंत्री महोदय ने सोचा है? ठीक है कि हैंडलूम का निर्यात बढ़ रहा है लेकिन गरीब लोग जो गरीब तबका इसमें लगा हुआ है उसके उपचार के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? इस ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि हैंडलूम में जो गरीब लोग लगे हुए हैं, उनकी समृद्धि के लिए वे कुछ प्रयास करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

मौलाना हबीबुर्रहमान नौमानी (नामनिर्देशित) : मोहतरमा वाइस चेयरमैन साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस मौजू पर तकरीर करने का मौका दिया।

मोहतरम, सबसे पहले मैं कपड़ा मंत्री जी के बारे में कहूंगा कि अब तक, इनके पहले तक, जो भी कपड़ा मंत्री आए, उनसे कहीं ज्यादा इन्होंने कपड़ा मंत्री की हैसियत से दिलचस्पी ली। यह अलग बात है कि बुनकरों को जितना फायदा, मंत्री जी तो है ही नहीं...

उपसभाध्यक्ष (श्री स्तीश अग्रवाल) : बैठे हैं।

मौलाना हबीबुरहमान नौमानी : जितना फायदा बुनकरों को पहुंचना चाहिए था वह पहुंच नहीं सका और उसकी वजह नौकरशाही है। हमारे कपड़ा मंत्री जी कैसे इनके बहकावे में आते है उसकी एक मिसाल मैं देता हूं। कल मैंने स्पेशल मेंशन के जरिए जिक्र किया था कि 24 करोड़ 15 लाख रुपए के कर्ज को माफ करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनकी कोशिश से प्रधान मंत्री जी ने गोरखपुर के जलसे में ऐलान किया, केबिनेट में फैसला हुआ। उस मीटिंग में श्री मोती लाल बोरा जो उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं, भी थे और यह तय हुआ कि 46 करोड़ 15 लाख रुपए बुनकरों का माफ होगा, जिसमें 22 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार देगी और 24 करोड़ 15 लाख रुपया भारत सरकार देगी। 20 तारीख तक हमारे मंत्री महोदय को यही मालूम था। क्योंकि जब भी मैं पूछता था कि बुनकरों का कर्जा माफ नहीं हुआ, सोसाइटीज का तो माफ हो गया। लेकिन जिन बुनकरों ने इंडिविज्युअल कर्जा लिया था, उसमें से 5 फीसदी बुनकरों का भी कर्जा माफ नहीं हुआ है। मुझसे जबाब में यही कहा जाता था कि 24 करोड़ रुपया सेंटर से चला गया है और उत्तर प्रदेश सरकर ने वह रुपया नहीं दिया है। लेकिन 20 तारीख को जब इसकी खोजबीन हुई, तब यह बात साफ हो गई कि उत्तर प्रदेश सरकार ने तो 22 करोड़ रुपया दिया और उस रुपए से जितना कर्जा माफ हो सकता था वह माफ हुआ, जितना अदा होना चाहिए था वह अदा हुआ। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा नहीं गया। उसका एतराफ किया कपड़ा सैक्रेटरी ने और तब हमारे कपड़ा मंत्री जी को मालूम हुआ कि यह पैसा नहीं गया है।

मैं बहुत ज्यादा फिगर्स में नहीं जाना चाहता और अन्य सवालों पर भी नहीं जाना चाहता हूं। मैं तो सीधे-साधे सवाल करता हूं हमारे बहुत से भाई रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं कि हैंडलूम इसलिए मर रहा है कि रिजर्वेशन के ऊपर अमल नहीं हो रहा है। 20 तारीख का रिजर्वेशन के मसले पर मीटिंग थी। मैंने कहा कि हैंडलूम बंद है, पावरलूम बंद है तो फिर किसका रिजर्वेशन ? "सूत न कपास, लटठम लट्ठा।" बैठे हो रिजर्वेशन करने, हैंडलूम भी बंद, पावरलूम भी बन्द। कुछ बन ही नहीं रहा है तो रिजर्वेशन कैसा ? हमारे मंत्री जी ने बुनकरों के ऊपर बड़ी ही मेहरबानी की और यह ऐलान किया कि हम 20 रुपया पर के० जी० सूत के ऊपर सब्सिडी देंगे। इस तरह से 5 के० जी० सूत के बंडल पर 100 रुपया और 4 के० जी० 500 ग्राम के बंडल पर 90 रुपया छूट देंगे। इतना सस्ता सूत मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि यह मेहरबानी या यह राहत क्या बुनकरों तक पहुंची ? अप्रैल के महीने में एक दर्जन से ज्यादा बुनकर सैक्टरों का मैंने दौरा किया है। हर जगह यही शिकायत रही। टी० वी० पर हमने सुना, अखबार में हमने पढा, वह सूत कहां गया। हमको तो ऊंगली पर लपेटने के लिए भी एक धागा नहीं मिला। मैं जानना चाहता हूं कि नेशनल हैंडलूम फैडरेशन जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश में सूत दिया गया है या जिस एजेंसी के जरिए सूत दिया गया है, वह सूत कहां गया ? किसके पास गया ? हां, एक जगह मालूम हुआ। मुरादाबाद में एक कस्बा-नौगावां सादात है। वहां बुनकरों ने यह बताया कि यूपिका के जरिए हमको सूत मिला। लेकिन जब हम कपड़ा लेकर के आए तो जितनी सब्सिडी थी उसके लिहाज से जितनी कम लागत आ रही थी उतना दाम काट लिया गया। मतलब यह कि सब्सिडी की राहत बुनकरों को न मिलकर यूपिका को मिल गई या उसने हड़प कर लिया। यह सब क्या हो रहा है ? मंत्री जी

की नीयत बहुत सही है । वह चाहते हैं, वह गरीब परिवार से आए हैं, बुनकरों के बीच से आए हैं, चाहते हैं वहां तक पहुंचाना । लेकिन नौकरशाही पर अगर अंकुश नहीं हुआ तो यह नहीं चलने का है । मैं सबसे पहले तो यह कहूंगा, मंत्री जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि हमने बुनकरों के लिए कर्जा दिलाने का साधन किया है रियायती दर के ऊपर, कम इंटरेस्ट के ऊपर । लेकिन जो बुनकर डिफाल्टर हैं और अमीन और तहसीलदार के डर के कारण घर से भागते हैं उनको क्या फायदा पहुंचेगा ? क्या आप उनको कर्जा देंगे ? तो सबसे पहला काम यह है कि वह 24 करोड़ रुपया जाना चाहिए और जैसा कि प्रधान मंत्री जी ने ऐलान किया है, वायदा किया है, उस वायदे को पूरा होना चाहिए, कर्जा बिल्कुल माफ होना चाहिए । तब जाकर के स्थिति सुधरेगी । एक बात मैं और कहना चाहता हूं । मुझे थोड़ा दो मिनट का मौका दें क्योंकि मसला बहुत उलझ रहा है । यहां पर हमारे जो सीनियर मैंबर हैं, वे हैंडलूम और पावरलूम की बात करते है । अजीब मज़ाक की बात है । एक तरफ तो यह कहा जाता है कि एक करोड़ रुपया दिया जाए बुनकरों को, स्पिनिंग जो छोटी मशीन है, वह लगाए 32 स्पिंडल की । किसान का हिंदुस्तान के अंदर खेती के बाद सबसे बड़ा जरिया जो है यह कपड़े की सनत है । अगर किसान ट्रैक्टर चलाता है, हल नहीं चलाता हल को छोड़ रहा है तो अगर बुनकर जो है, हथकरघा को छोड़कर के शक्तिचलित करघा इस्तेमाल करता है पावरलूम इस्तेमाल करता है तो फिर क्या ऑब्जेक्शन है ? जो आप सबिसडी देते हो, जो आप राहत देते हो हल चलाने वाले किसान को, वही राहत देते हो ट्रैक्टर चलाने वालों को तो क्यों नहीं देते हैंडलूम को जो राहत देते हैं, पावरलूम को भी ?

एक बात और साफ करना चाहता हूं । पावरलूम दो तरह के हैं । एक तो वह है जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हैं । एक मकान के अंदर या एक जगह, दस, बीस, पच्चीस, पचास पावरलूम लगे हुए हैं और एक हैं डोमेस्टिक पावरलूम, घरेलू पावरलूम, जो घर में शौहर, बीवी, बच्चे मिल करके चलाते हैं ।

मैं और साफ करना चाहता हूं कि अगर आप बुनकरों को राहत देना चाहते हो तो उनको दरिद्र बनाने की कोशिश मत करो । अगर वे पावरलूम लगाते हैं तो उनको पावरलूम लगाने का मौका दो । एक आदमी हैंडलूम पर जो काम करता है वह ज्यादा से ज्यादा पचास रुपए का काम करता है । मंहगाई इतनी है, कम से कम पांच आदमी होते है घर में, पचास रुपए से क्या काम चल सकता है ? लेकिन वही बुनकर जब पावरलूम लगा लेता है, आपकी सहायता से लगाता है, आपकी मदद से लगाता है तो उसकी इनकम सौ रुपए से लेकर दो सौ रुपए तक होती है । बिल्कुल वैसे ही जैसे हल चलाने वाले किसान और ट्रैक्टर चलाने वाले किसान की आमदनी में फर्क होता है । इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि बीस बरस, पच्चीस बरस, पचास बरस पीछे मत देखो, आगे देखो । उलटी गंगा बहाने की कोशिश मत करो । लोगो की गरीबी दूर करना चाहते हो तो उनकी मदद करो कि वे पावरलूम लगाएं ।

इसी सिलसिले में मैं एक बात और कहना चाहता हूं । जब यूपिका का जिक्र आ गया तो मैं कहना चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की यह जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बुनकरों के लिए यह हैंडलूम कारपोरेशन और यूपिका जो बनाया गया था, उस पर नज़र डाले, क्या है इसका हाल यूपिका के अंदर पांच-पांच बरस से बुनकरों का रुपया बकाया है, मिल नहीं रहा है और मैं समझता हूं कि जितनी उनकी लायबिलिटी है, जितनी उनकी जिम्मेदारी है, वे अदा भी नहीं कर सकते हैं । मैं तो यह कहूंगा मंत्री जी से कि वे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को, वहां के हैंडलूम मंत्री को बुलाएं और यह फैसला लें कि यूपिका और हैंडलूम कारपोरेशन तोड़ दिया जाए । नया कोई आर्गेनाइजेशन बनाया जाए

बुनकरों के लिए तब तो बुनकरों को राहत मिल सकती है वरना जो कुछ भी आप कर रहे हैं, उससे फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए बातें तो बहुत कहने की हैं। मैं देख रहा हूं कि आप बार-बार उचक रहे हैं, माफ करेंगे उचकने का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया मैंने, देख रहे हैं। तो मैं अपनी बात बहुत ज्यादा न कह कर एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि जैसा कि मैंने कहा कि सबसिडाइज्ड सूत बुनकरों को मिल नहीं रहा है। क्या मैं उम्मीद करूं कि कपड़ा मंत्री जी जगह-जगह जो हैंडलूम सेंटर हैं, पावरलूम सेंटर हैं, जो सूत इस्तेमाल करते हैं, वहां डिपो कायम करके कार्ड बनवा करके न पूरा सूत दें, एक ही बंडल दो भाई, दो बंडल दो। अगर चार बंडल का खर्चा है पचास फीसदी दो, पच्चीस फीसदी दो। बुनकरों के नाम पर सबसिडी के नाम पर अरबों रुपया चला जाए और बुनकर को उसका एक कतरा न मिले, इसलिए मैं यह चाहता हूं कि जो आज के हैंडलूम के मसायल हैं, जो बुनकरों के मसायल हैं सचमुच बुनकरों की जो हालत है, शहर में बैठ करके हम नहीं देख सकते हैं। कस्बों में जाइए, देहातों में जाइए, जो फनकार हैं, जो कारीगर हैं आज सड़कों पर पत्थर की गिट्टी तोड़ रहे है।

वे भागकर बड़े-बड़े शहरों में जाकर मेहनत और मजदूरी कर रहे हैं। इन सब हालातों से बुनकर गुजर रहे हैं। मैं यह चाहूंगा कि उनकी तरफ तवक्को दिया जाए। सबसे पहला काम तो आप यह कीजिए कि 24 करोड़ रुपया जो बुनकरों पर कर्जा है, उस कर्ज से उनको मुक्ति दिलाई जाए और उसके बाद इस बात का पक्का बंदोबस्त किया जाये कि यह जो रियायती दर का सूत है, वह बुनकरों को मिले और जो उनका माल है उस माल को बेचने का पक्का बंदोबस्त किया जाए। इसके लिए अगर जरूरी हो तो हैंडलूम कारपोरेशन और एपको को तोड़ दिया जाए और सूबों में जो एजेंसियां ठीक से काम नहीं कर रही हैं उनकी जगह पर नयी एजेंसियां कायम की जाये ताकि उनको कारगर बनाया जा सके और जो लोग इसमें लगे हुए हैं उनको भुखमरी के शिकंजे से बचाया जा सके।

+[مولانا حبیب الرحمان لنعمانی "تامزد"
محترم وائس چیرمین صاحب۔
سب سے پہلے تو میں آپکا شکریہ
ادا کرتا ہوں کہ اپنے معمولہ اس
موقعہ پر بولنے اور تقریر کرنے کا
موقعہ دیا۔
محترم سب سے پہلے میں کپڑا منتری
جی کے بارے میں کہونگا کہ آپ
انکے پیارے ہیں۔ چیرمین کپڑا
منتری اتنے ان سے بہیں زیادہ
ایون نے کپڑا منتری کی حیثیت سے
دلچسپی لی۔ یہ ایک بات ہے کہ بنکروں
کا زیادہ فائدہ۔ منتری جی تو بس ہی
نہیں
اب سچا ادھیکش "منتری سنیش
اگروال" بیٹھے ہیں۔
مولانا حبیب الرحمان: جتنا فائدہ
بنکروں کو پہونچنا چاہیئے تھا۔ وہ
پہونچ نہیں سکا اور اسکی
وجہ نوکر شاہی ہے۔ ہمارے
کپڑا منتری جی بیکار میں اتنے
ہیں۔ اس کی ایک مثال میں دیتا
ہوں۔ کل میں نے اسٹیل منسٹر
کے بارے ذکر کیا تھا کہ ہم نے سروے
10 لاکھ روپیے کے قرض کو معاف

+[ ]Transliteration in Arabic Script

نے وہ روپیہ نہیں دیا ہے۔
لیکن ۲۰ مارچ کو جب
اسکی کوئی نہیں ہوگی۔ تب
یہ بات صاف ہوگی کہ انڈھرپردیش
سرکار نے تو ۲۲ کروڑ روپیہ
دیا اور اس روپیہ سے جو
قرض معاف ہوسکتا تھا
وہ ہوا۔ جتنا ادا ہونا
چاہیے تھا وہ ادا ہوا۔
لیکن سنٹرل گورنمنٹ سے
پیسہ نہیں لیا۔ اسکا
اعتراف کیا گیا۔ منتری جی
کو معلوم ہوا کہ یہ پیسہ نہیں
گیا ہے۔

میں بہت زیادہ ٹیکنیکل
میں نہیں جانا چاہتا اور اپنے
سوالوں پر بحث نہیں جانا چاہتا
ہوں۔ میں تو سیدھے سیدھے سوال
کرتا ہوں۔ کیا ہماری بہت بھاری
دفدرشن کی بات نہیں ہے کہ ہندو اسلام
ہوتا ہے کہ دوردرشن کے اور فل نہیں
ہو رہا ہے۔ ۲۰ مارچ کو دوردرشن
کے لئے پریمنگ تھی میں نے کہا کہ
ہندو دھرم بندھے۔ باوا۔ دھرم
بندھے۔ تو پھر کس کا دوردرشن۔

کرنے کیلئے سنٹرل گورنمنٹ
نے انکی کوشش سے پردھان منتری
جی نے گودھیورے جیلے
میں اعلان کیا۔ لیٹ میں
نتیجہ ہوا۔ اس میٹنگ میں
منتری موتی لال ووڑا جو
انڈھرپردیش کے گورنر ہیں بھی
تھے۔ اور یہ طے ہوا کہ ۸۶
کروڑ ۱۵ لاکھ روپیہ بنکروں کو
معاف ہوگا۔ جس میں ۲۲ کروڑ
روپیہ انڈھرپردیش سرکار دیگی
اور ۶۴ کروڑ ۱۵ لاکھ روپیہ
بھارت سرکار دیگی۔ ۲۰ تاریخ
تک بھارت منتری مہودے کو بھی
معلوم تھا۔ کیونکہ جب بھی میں
پوچھتا تھا کہ بنکروں کا قرض معاف
نہیں ہوا۔ سوسائٹی کا بھی معاف ہوگا۔
لیکن جن بنکروں نے انڈر ویئر
فرصہ لیا تھا ان میں سے ۵۰
فیصدی بنکروں کا بھی قرض
معاف نہیں ہوا ہے۔
مجھ سے جب میں بھی
کہا جاتا تھا کہ ۲۲ کروڑ
روپیہ سنٹر سے چلا گیا ہے
اور انڈھرپردیش سرکار

†[ ] Transliteration in Arabic script.

ہے - یا جس ایجنسی کے ذریعے
سیوت دیا گیا ہے - وہ سیوت
کہاں گیا - کس کے پاس گیا -
یاں - ایک جگہ معلوم ہوا -
منتری - مراد آباد میں ایک لیبر
نرگاداں یاد دت ہے - وہاں
بنکروں نے یہ بتایا کہ روپیہ
کے دور سے ہم سیوت ملا - لیکن
جب ہم پیڑا لیکر اتنے تو جتنی
سیڈی تھی انکے لحاظ سے جتنی کم
لاگت آدمی تھی - اتنا دام کاٹ
لیا گیا - مطلب یہ کہ سیڈی کی
راحت بنکروں کو نہ ملی کہ پورا
کو ملا گئی یا اس نے ہڑپ کر لیا -
یہ سب کیا ہو رہا ہے - منتری
جی کی نعمت بہت اچھے ہے -
وہ ہمیشہ پریوار سے آگے
ہیں - بنکروں کے بیچ سے آگے
ہیں - جاتے ہیں وہاں تک
پہونچنا - لیکن تو وہاں پر اگر
ایکسٹینشن نہیں ہوا تو یہ نہیں چلے گا ہے -
میں سب سے پہلے تو یہ کہونگا - منتری
نے بڑی اچھی بات کہی کہ
ہم نے بنکروں کیلئے فلاں فلاں
کا سا دھن کیا ہے - ہمارا نیں
دوکے اور - کہ انسٹرسٹ

سوت نہ لیا سن لوم لگا سکے
ہو رہو ویشن کر نے - بنتر لوم
بھی بند - پاور لوم بھی بند -
کچھ بن بھی نہیں رہا ہے تو افرو ویشن
کیا ہمارے منتری جی نے بنکروں
کے اوپر پیڑی ہی مہربانی کی اور
یہ اعلان کیا کہ ہم ۲۰ اوپیے پر
کے بھی سوت کے اوپر سبسیڈی
دینگے - اسطرح سے لگے بھی
سوت کے بنڈل پر ۱۰۰ روپیہ اور
کے بھی ۵۰۰ گرام کے بنڈل پر ۵۰
روپیہ چھوٹ دینگے اتنا سستہ
سوت ملیگا - میں پوچھنا چاہتا
ہوں کہ یہ مہربانی یا یہ راحت کیا
بنکروں تک پہنچ رہی ہے - پریوار کے بیچ میں
ایک درجن سے زیادہ بنکروں
کا میں نے دورہ کیا ہے - ہر جگہ میں حقیقت
یہی ہے - ٹی - وی - پر ہم نے سنا - اخبار
میں ہم نے پڑھا - وہ سوت
کہاں گیا - ہم کو تو انگلی پر
گننے کیلئے بھی ایک دھاگا

نہیں ملا - میں جاننا چاہتا
ہوں کہ ٹیکسٹائل منتری نے
فیڈریشن کے ماد ھم سے
رہنو ویشن میں سوت دیا گیا

†[] Transliteration in Arabic script.

بنکلو جو ہے سنکلر لگا کر چھوڑ کر کے تلسی
نالی کو اچھا استعمال کرتا ہے - پاور لوم
استعمال کرتا ہے تو پھر کیا آبلیشن ہے -
جو آپ سبسڈی دینے ہیں جو آپ
راحت دیتے ہیں بل جلانے والے کسان کو
وہی راحت دیتے ہیں بنکلو جلانے والوں
کو تو کیوں نہیں دیتے ہینڈلوم کو
جو راحت دیتے ہیں پاور لوم کو بھی -
ایک بات اور صاف کرنا چاہتا ہوں -
پاور لوم دو طرح کے ہیں - ایک
تو وہ ہیں آرگنائزڈ سکٹر
میں ہیں - ایک مکان کے اندر
یا ایک جگہ - دس بیس - پچیس
پچاس پاور لوم لگے ہوتے
ہیں - اور اب یہی در حقیقت پاور لوم - کم سے
پاور لوم - جو گھر میں منتشر - بیوی بچے مل کر
کے چلاتے ہیں

میں اور صاف کرنا چاہتا ہوں کہ
اگر آپ بنکروں کو راحت دینا چاہتے
ہیں تو انکو مزدور بنانے کی کوشش مت کریں
اگر وہ پاور لوم لگاتے ہیں تو انکو پاور
لوم لگانے کا موقعہ دو -

اب اس ہینڈلوم پر جو کام کرتا ہے
وہ زیادہ سے زیادہ پچاس روپئے کا
کام کرتا ہے - مہنگائی اتنی ہے - کم سے
کم پانچ آدمی ہوتے ہیں گھر میں -
کے اور - لیکن جو بنکر فالٹ ڈی
فالٹ میں اور اس تعلیدار کے
ڈر سے کارن گھر سے بھاگے ہیں انکو
کیا فائدہ پہنچیگا - کیا آپ انکو قرضہ
دینگے - تو سب سے پہلا کام یہ
کہ وہ ۲۲ کروڑ در دب جانا چاہیئے -
اور جیسا کہ پردھان منتری جی نے
کیا ہے - وعدہ کیا ہے - اعلان کیا
ہے - وعدہ کیا ہے - اس وعدے
کو پورا ہونا چاہیئے - قرضہ
بالکل معاف ہونا چاہیئے - تب
جاکر اسکتی سدھر پائیگی -

ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں
مجھے تھوڑا وقت کا موقعہ دیں -
کیونکہ سلسلہ الجھ رہا ہے -
بیان بھارے جو سب نیوز میں -
وہ ہینڈلوم اور پاور لوم کی
بات کرتے ہیں - عجیب مذاق کی بات
ہے - ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے - کہ ایک
کروڑ روپیہ دیا جائے بنکروں
کو - اسکیم جو چھوٹی منی ہے - وہ
لگائیں ۲۲ اسٹیٹ کی - کسان کا
ہندوستان کے اندر کھیتی کے بعد سب
سے بڑا ذریعہ جو ہے یہ کپڑے کی صنعت
ہے - اگر کسان ٹریکٹر چلاتا ہے - بل نہیں
چلاتا - بیل کو چھوڑ دیا ہے - تو اگر

†[] Transliteration in Arabic script.

منتری تو وہاں کے ہینڈلوم منتری کو بلائیں اور فیصلہ لیں کہ پیریکا اور ہینڈلوم کا ریپوریشن توڑ دیا جائے۔ نیا کوئی اور کارپوریشن بنایا جائے بنکروں کیلئے تب تو بنکروں کو راحت مل سکتی ہے۔ ورنہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں۔ اس سے فائدہ ہونے والا نہیں ہے اسلئے باتیں تو بہت ہو چکی ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بار بار اچھا رہے ہیں میں صاف کر دیتے اچھے کے لفظ کا استعمال کر لیا میں نے دیکھا ہے میں تو اپنی بات

بہت زیادہ نہ کہہ کر ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ مسٹر انڈر سیوٹ بنکروں کو مل رہا ہے۔ کیا میں امید کروں کہ پیر امنتری جی جگہ جگہ جو ہینڈلوم سنٹرز ہیں۔ پاور لوم سنٹرز ہیں۔ جو سیوٹ استعمال کرتے ہیں وہاں ڈپو قائم کر کے۔ کارڈ بنوا کر نہ پورا سیوٹ لیں ایک ہی بنڈل دو کھلائی۔ وہ بنڈل دو اگر چار بنڈل کا خرچہ ہے پچاس فیصدی دو پچیس فیصدی دو بنکروں کے نام پر ہو مسٹر کے نام پر ادیوں روپیہ ملا جائے اور بنکروں کو اسکا ایک فائدہ نہ ملے۔

پچاس روپیہ سے کیا کما سکتا ہے۔ لیکن وہی بنکر جب پاور لوم لگا لیتا ہے۔ آپکی سہائتا سے لگا لیتا ہے۔ آپکی مدد سے لگاتا ہے۔ تو اسکی آمدنی سو روپیہ سے لیکر دو سو روپیہ تک ہوتی ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے ہل چلانے والے کسان اور ٹریکٹر چلانے والے کسان کی روزی میں فرق ہوتا ہے۔ اسلئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیس برس پچیس برس پچاس برس سمجھیے مت دیکھیے آگے دیکھیے۔ اس گنگا بہانے کی کوشش مت کرو۔ لوگوں کی غریبی دور کرنا چاہتے ہو تو اتنی مدد کرو کہ وہ پاور لوم لگا سکیں۔

اس کے علاوہ میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں۔ جب پیریکا کا ذکر ہوا تھا تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ مسٹر ڈل نے کہا تھا کہ یہ ذمہ داری ہے کہ اتر پردیش کے اندر بنکروں کیلئے یہ ہینڈلوم کا ریپوریشن اور پیریکا جو بنایا گیا تھا۔ اس پر نظر ڈالیں۔ کیا ہے اس کا حال۔ پیریکا کے اندر پانچ پانچ برس سے بنکروں کا روپیہ بقایا ہے۔ مل نہیں رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی انکی لاسٹی ہے۔ جتنی انکی ذمہ داری ہے وہ ادا بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ میں تو یہ کہونگا کہ منتری جی سے کہ وہ اتر پردیش کے بجائے

†[] Transliteration in Arabic script.

श्रीमती कमला सिन्हा (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया । मैं उन माननीय सदस्यों, जिन्होंने आज के कालिंग अटेंशन मोशन की चर्चा में भाग लिया है, उनको भी में धन्यवाद देता हूं । बुनकरों की जो दुर्दशा है उसकी ओर उन्होंने मंत्री जी की ध्यान खींचा है । मंत्री जी ने इस पर लंबा बयान दिया है । आंकड़े बहुत दिए लेकिन में आंकड़ों के जंगल में नहीं जाना चाहती और न उन बयानों में से कुछ उद्धृत करना चाहती हूं क्योंकि बातें बहुत हो चुकी हैं । मैं केवल कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी ।

यह बात सत्य है कि कृषि के बाद शायद, हैंडलूम इस देश में सबसे ज्यादा लोगों को नौकरी देता है । लगभग 80—85 लाख लोग इस काम में जुड़े हुए हैं । यह कृषि जनित उद्योग है और गांव में, छोटे-छोटे इलाकों में, कस्बों में यह फैला हुआ है । हमने देखा है कि कैसे दुर्दशा में लोग रह रहे हैं । पिछले

दिनों आंध्र प्रदेश में भुखमरी के कारण लोगों की मौतें हुई थीं, यहां पर यह सवाल कोटैया जी ने सदन में उठाया था। अखबार और मैगजीनों में यह बात आयी थी। हम लोग वहां जांच के लिए गए थे। सब की वहां बुरी हालत है, दुर्दशा है। पूरे देश में बुनकर दुर्दशा की हालत में रह रहे हैं। यह ठीक है कि नेशनल हैंडलूम कारपोरेशन बना हुआ है। लेकिन यह हैंडलूम कारपोरेशन सचमुच में कारगर नहीं है। मंत्री जी को चाहिए कि हडलूम कारपोरेशन जो है उसको री-आर्गनाइज करें। आज का यह जो हैंडलूम कारपोरेशन है उससे काम नहीं चलेगा। एक लूम को, एक नए लूम को एक वर्कशाप को बनाने के लिए 8 हजार रुपये बुनकरों को मिलते हैं। बुनकरों से बैंक वाले यह कहते है कि पहले 4 हजार रुपये दो, फिक्स डिपोजिट करो। लेकिन अगर फिक्स डिपोजिट के लिए इतना रुपया बुनकरों के पास होता तो वह बैंक से लोन लेंगे क्यों। यह बात हमने पोचनपल्ली गांव में सुनी और हमें आश्चर्य हुआ कि हैंडलूम वीवर्स की कोआपरेटिव सोसायटी हुई है और काआपरेटिव सोसायटी के माध्यम से धागा मिलता है और इन्हीं कोआपरेटिव सोसायटी के माध्यम से कपड़ा बेचना होता है। लेकिन ये कोआपरेटिव सोसाइटीज कपड़ा नहीं बेच रही हैं। टाल के टाल लगे हुए हैं लेकिन बाजार में बिक नहीं रहा है, कोई डिमांड नहीं हैं। आंध्र में एपको हैं, तमिलनाडु में भी हैंडलूम कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं और कर्नाटक में भी हैं। हमारे उत्तर भारत में भी हैं लेकिन वास्तव में, ये जो सोसाइटीजें हैं ये बिक्री के केन्द्र नहीं बन पा रही हैं, सामान बिक नहीं रहा है। नतीजा यह है कि हैंडलूम वीवर्स दुर्दशा की हालत में हैं। मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में हैंडलूम सेक्टर के डेवलपमेंट के वेलफेयर के संबंध में बात की है। लेकिन आप उनका वेलफेयर कैसे करेंगे ? मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं जहां तक उनके बच्चों की पढ़ाई का सवाल है, उनके बच्चे एक कोठरी में रहते हैं और एक कोठरी में लूम चलता है। उनकी दुर्दशा उनकी हालत क्या रहती है कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं होती और ना ही उनके स्वास्थ्य की ठीक से देखभाल होती है। इस दिशा में बीड़ी और सिगरेट मजदूर जो हैं उनके लिए बीड़ी-सिगरेट वर्कर्स ऐक्ट बना हुआ है। इसके तहत एक प्रावधान किया गया है कि कामगारों को आइडेंटीकार्ड मिलेगा।

जिसके पास आइडेंटीटी कार्ड होगा, उसके लिए स्वास्थ्य सुविधा का भी प्रावधान किया जाएगा। मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या आप हैंडलूम वीवर्स के लिए कोई इस तरह का कानून बनायेंगे और उन लोगों को कोई आइडेंटिटी कार्ड वगैरह देंगे जिससे उनके स्वास्थ्य की देखभाल हो सके ? क्या उनके बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के लिए निश्चित कार्यक्रम अपनाएंगे जिससे उनको वेलफेयर का काम अच्छी तरह से आगे बढ़ सके और आने वाले बच्चे दुर्दशा की हालत में नहीं रहे। तीसरी बात, मैं यह जानना चाहती हूं कि जो सिल्क वीवर्स हैं, काटन टैक्सटाइल वीवर्स हैं, इनकी कला कहीं मर न जाए, इनकी कला जीवित रहे, इसके लिए आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर अधिक बल देंगे जिससे कोई नयी विधि तैयार हो सके और इनका माल स्टॉक न होने पाए और आउट-डेटेड न होने पाए और बाजार में उसकी ठीक ढंग से बिक्री हो सके। क्या आप यह काम करेंगे, यह मेरे तीन सवाल हैं जिनका उत्तर मैं मंत्री जी से चाहती हूं। इसके साथ एक बात और मैं यह कहना चाहती हूं कि सरकार का जो रवैया है उससे अपने देश की टैक्सटाइल इंडस्ट्री सचमुच मर जाएगी। मंत्री जी के मन में चाहे जितनी भी इच्छा हो लेकिन सरकार की पॉलिसी ऐसी हो गई है कि पोलिस्टर यार्न और सिंथेटिक यार्न को बढ़ावा मिलता जाएगा। हमारा जो कल्चर आ रहा है वह पोलिस्टर और सिंथेटिक यार्न का कल्चर पनप रहा है। उससे हट कर अपने देशी उत्पादन को खरीदने के लिए हैंडलूम की सामग्री की बिक्री बढ़े, इसके लिए कोई ठोस कदम या

पॉलिसी डिसिजन क्या सरकार लेगी ? क्या मंत्री जी, कोई कारगर कदम इस दिशा में उठायेंगे ? यह मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं ।

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Mr. Vice-Chairman, thank you for giving me this opportunity to participate in the discussion.

THE VICE-CHAIRMAN: (SHRI SATISH AGARWAL): I was under the impression that Mr. Narayanasamy will have a meeting with Mr. Venkat Swamy to discuss matters.

SHRI V. NARAYANASAMY: I want the discussions to be held in the House and not privately with the Minister. Sir, as far as problems faced by the handloom weavers are conterned, the Minister knows it well. Unfortunately, Sir, the Annual Report for 1994-95 that has been submitted to Parliament has been reproduced in the statement of the hon. Minister. Sir, if you go through the Annual Report and the statement of the hon. Minister you will see that there is no further improvement. Otherwise, the hon. Minister would have laid on the table of the House the Annual Report for the year 1994-95. Sir, the basic problem of the handloom weavers as raised by Mr. Pragada Kotaiah is the short supply of hank yarn to the weavers. This is being faced by all the States. Apart from that the price has been increased because of the support of the hank yarn beyond the limit that has been prescribed by the Ministry. And the Minister says that he is giving subsidy. The basic problem is that the weavers who are doing it at the village level take the yarn from the cooperative societies. They weave the yarn, bring the cloth and give it to the society. Then they get the wages. The cooperati society system is going on and the income is given to them on a weekly basis which our Minister knows. The cooperative societies are not in a position to pay even on a weekly basis. It goes even to months because they are not able to sell their products in the market. The Minister says that the Handloom Promotion Council is there and we have got a system by which we are helping them. As far as hank yarn is concerned, since the prices are going up and no proper support is coming some of the cooperative societies have been closed down. They are being closed and the weaving community who have been depending upon weaving only go to the private individuals for the purpose of getting yarn and then they weave and supply to them. So, the weavers are being exploited by the persons who are exporting the cloth, by the private agencies. This is the problem. *Apart from that the hon. Minister* gave the figures of prosecutions. The Minister says, "Those who have not followed the Handloom Reservation *Order, action has been taken* against them, the FIR has been filed." That came into force in 1986. Then the new Textile Policy was announced by the Government and the Minister said. "The matter is pending at the FIR stage." Sir, the handloom lobby, I fully agree with Shri Kotaiahji, is so powerful like the powerloom, and the hon. Minister could not withstand the pressure from the power sector and ultimately the poor handloom weavers, who have no organising capacity for fighting against the Textiles Ministry, for fighting against the powerful powerloom sector, they are the real sufferers. Then what is the welfare measure that they have implemented for them? Sir, the hon. Minister says—I went through the Annual Report—the 20-Point Programme that has been implemented by the Government has also been extended to them. It is not under the mercy of the Textiles Ministry The people who are really to be the beneficiaries under the DRDA scheme or the Jawahar Rozgar Yojana or the IRDP, for the purpose of their development, they can get it. Why should they go to the Textiles Ministry?

Sir, I would like to ask: Out of the 124 lakhs even 25 lakhs are handloom weavers in this country, how

many colonies have, they provided for them whether it is in Tamil Nadu or Andhra Pradesh, the State from which the hon. Minister comes? Sir they have constructed about 2,000 houses but they have given a very big figure about it . Housing problem is a very big problem for the handloom weavers. The cooperative societies can be encouraged by bringing a scheme to give benefit and to give regular employment to the handloom weavers, to give them at least 20 days work. There is no mechanism for giving them employment through the cooperative societies at the State level. Therefore, Sir, I agree that the Minister is taking keen interest. But, unfortunately, the Ministry is misleading the Minister and the Minister goes by the figures that have been given by them. The Minister goes to the slums where the weaving community is living. He understands their problems. Even today most of them are living in the thatched huts. I know it because we have been visiting there. Their salary does not exceed more than Rs. 70 to Rs. 80 per week. How can a family live on this Rs. 80? How can they send their children to school and maintain their family. How are they to live? The hon. Minister has to understand it. What is the problem in allocating the required quantity of hank yarn to the handloom sector? What is the problem? You have to gear up the machinery at the State level. You are having agencies at Madras, Calcutta and Delhi. What are they doing? Filing FIRs will not do. You will have to cancel the licences of the importers in the powerloom sector, who are violating the norms and who are violating the guidelines. Why are you not doing it? As a result of this, they get emboldened. You are not able to implement the order that has been issued by your Ministry. Sir, therefore, the problem faced by the handloom weavers is very serious. There are starvation deaths. The Minister knows it. Fortunately for us, it is not there now, because the Minister is taking keen interest. But, still he has to do a lot of work. Let him not go by what the Ministry says. He should apply his mind to the various problems which are being faced by the handloom weavers and then try to help the handloom weavers to the maximum extent possible. Sir, I will conclude with one more point. Sir, marketing is the biggest problem for the handloom sector.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): You are putting forward a dangerous proposition. If the Minister does not go by what the Ministry says then the Ministry will not go by what the Ministry says.

SHRI V. NARAYANASAMY: Therefore Sir, I said, that there should be close coordination between the Minister and the Ministry.

SHRI ANANT RAM JAISWAL (Uttar Pradesh): He says that the Minister does not apply his mind.

SHRI V. NARAYANASAMY: I did not say that. I said that 'the Ministry is misleading the Minister'. That is what I said. In spite of the fact that the Minister knows the ground realities, he is being misled by the Ministry. That is my point. I now come to the marketing aspect. The basic point is this. When hank yarn is exported, we get a lesser amount. On the other hand, if value-addition is there, we can get double that amount. The Government's policy is to see that there is value-addition. At the same time, we are exporting only yarn. There should be a correlation. The question is: Are you accepting the new economic policy of the Government or not? Is the Ministry of Textiles accepting the new economic policy of the Government or not? You give the yarn to the handloom weavers. Let them use of the yarn to make handloom

products. They can be exported so that the country would get more foreign exchange and the handloom weavers also would be able to get more income out of it. I do not say that you should stop exporting yarn. There should be a correlation between the two. There should be some limit.

SHRI G. VENKAT SWAMY: Mr. Gurudas Das Gupta is saying.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: I say 'reduce'.

SHRI V. NARAYANASAMY: I am also saying 'reduce'. I would like to tell the hon. Minister: 'Please don't fall a prey to the powerloom sector' Don't allow the powerloom sector to dictate terms to your Minisry.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: There should be a reduction in the exports, reckless exports.

SHRI V. NARAYANASAMY: Reduction in the export of hank yarn. I am not talking about the cloth. Kindly bear with me.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: I am also talking about yarn only.

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, what is happening today? The hon. Minister knows about it. A lot of spinning mills are coming up. The weaving mills are being closed down one by one. (*Interruptions*). This is the real situation. The hon. Minister knows about it. The big industrialists want to make quick money by producing only yarn, at the cost of the poor handloom weavers.

I know the hon. Minister is a very dynamic person. I have a great regard for him. But I want him not to be misled by his Ministry.

Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Shri Anantram Jaiswal.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Mr. Narayanasamy is saying, the Minister is so naive as to be led astray by his Ministry.

SHRI V. NARAYANASAMY: No, I am not telling that.

श्री अनन्तराम जायसवाल : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में हथकरघा उद्योग के विकास और बुनकरों की बेहतरी के लिए, भलाई के लिए बहुत सी स्कीमें और बातें बताई हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि इन सब के बावजूद क्या यह सही नहीं है कि सूती कपड़ा बनाने वाले जो बुनकर हैं उनकी आमदनी महीने में पांच सौ, छः सौ रुपये से ज्यादा नहीं है और जो रेशमी कपड़ा बनाते हैं उनकी आमदनी 700–800 रुपये से ज्यादा नहीं है ? क्या यह बात सही है और उनकी जानकारी में आई है ? अगर यह बात सही है तो इसका मतलब हुआ कि कुछ मास्टर वीवर्ज को छोड़कर सारे बुनकर बिलो पावर्टी लाइन रह रहे हैं और अगर वे रह रहे है इन सब तमाम स्कीमों के बावजूद तो उनको ऊपर उठाने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए कोई और आप करेंगे या नहीं ? दूसरी चीज मेरा ख्याल है कि आपकी जानकारी में यह बात आई होगी कि आज जो सूत बुनकरों को सप्लाई हो रहा है उससे उनको महीने में मुश्किल से 15 दिन काम मिलता है और यह सभी लोग जानते हैं, कोटैया जी हम से अच्छी तरह जानते हैं और आप भी जानते होंगे कि मुश्किल से 15 दिन का सूत उनको मिलता है और उसी के साथ सूत की कीमतें बराबर बढ़ रही हैं, तो आप यह बताइये कि जिस वक्त आपकी मौजूदा सरकार ने हकूमत संभाली उस वक्त सूत के क्या दाम थे हैंक्यार्न के विभिन्न तरह के जो धागे हैं, उनके दाम उस वक्त क्या थे और आज क्या हैं और 15 दिन के काम के लिए जो सूत की सप्लाई मिलती है इसको आप कैसे और बढायेंगे ?

तीसरी चीज जो है मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने नाबार्ड के री-फइनांस की बात कही कि नाबार्ड कर्जा देता है यह प्राइमरी सोसायटी, डिस्ट्रिक्ट सोसायटी वगैरह के जरिए, आप अच्छी तरह जानते

होंगे कि इनमें से बहुत सी सोसायटियां डी-फैक्ट हो चुकी है, काम नहीं करती नतीजा उसका यह होता है कि उनसे बंधे हुए जो बुनकर हैं उनको पैसा नहीं मिल पाता है। दूसरी चीज यह है कि जब यह सोसायटियां खुद कर्जदार हो गई हैं, तो नाबार्ड इनको पैसा नहीं देता है तो उसका असर होता है कि ये जिला स्तर की सोसायटियां और स्टेट लेवल की जो संस्थाएं हैं वे बुनकर को न तो सूत दे पाती हैं और न उनका माल खरीद पाती हैं। कनवर्शन चार्ज देने के बाद भी उनके माल की खरीद नहीं पाती है। नतीजा यह होता है कि बुनकर के पास और स्टेट लेवल की जो संस्थाएं हैं, उसके भी पास स्टॉक बराबर "पाइल अप" होता चला जाता है और इस तरह उनकी बिक्री नहीं हो पा रही है जिसकी वजह से, उपाध्यक्ष महोदय अभी हम "प्रकाशम" गए थे, कोटैया जी भी साथ थे प्रकाशम में करीब-करीब वही स्थिति है जोकि 1992 में थी। इस हालत को दुरुस्त करने के लिए क्या आप बैंक पर दबाव डालेंगे कि स्टेट लेवेल की जो संस्था है, वह उसकी लिमिट कुछ बढ़ा दे? दूसरे जो "डिफैक्ट" सोसायटीज हैं, अगर उनको पैसा नहीं मिलता है, तो जैसाकि व्यवस्था की गयी है कॉर्नशियल बैंक्स के जरिए भी "नाबार्ड" बुनकरों को पैसा बांटे। उपसभाध्यक्ष महोदय एक चौथी चीज यह है कि जहां बंटवारा किया गया था संरक्षण दिया गया था कि कुछ चीजें खाली हथकरघा उद्योग में ही बनें, लेकिन लोग बताते हैं कि वह कानून मुबहम है, एम्बीगुअस है और नतीजा यह है कि यह साफ ही नहीं हो पाता है कि कौनसी चीज हथकरघा उद्योग बनाएगा कौनसी चीज पावरलूम बनाएगा और कौनसी चीज मिल बनाएगा इस तरह यह सारा मामला घालमेल में बहुत दिनों से पड़ा हैं। म आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना ऑर्डर कर दिया है और इस कानून को वैलिड मान लिया है, लेकिन अभी तक स्टेट लेवल पर मेरा ख्याल है कि किसी भी जगह पर चाहे वह आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या आपका कर्नाटक हो, कहीं पर भी इस कानून का मिफाज नहीं हो रहा है। इसलिए उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर ऐसी एंबिगुइटी कानून में हैं तो उसे दूर करने के लिए आप उस कानून में तुरंत संशोधन कीजिए और दूसरे जो देश को राज्य सरकार हैं उनके ऊपर आप दबाव डालें कि वे इस कानून का सख्ती से पालन करें अगर आप हैंडलूम को बचाना चाहते हैं तो।

मान्यवर, एक दुर्भाग्य की बात यह है कि हैंडलूम वीवर्स का जो हुनर है, उसको कद्र सारी दुनिया ने की है और उनके हुनर की मांग है और उनके प्रोडक्ट की भी मांग है। तो वे अपने प्रोडक्ट को भेज सकें इसके लिए वे क्यों दूसरों के मोहताज हों? इसलिए या तो सरकार कोई व्यवस्था करे या उनके बीच से कोई ऐसा संगठन खड़ा किया जाय कि जिसके माध्यम से वह अपने माल को विदेशों में भेज सकें। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय, इन मुद्दों पर प्रकाश डालें। उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Before I ask the Minister to reply, does any other Member want to seek some clarifications or put some questions?

श्री शंकर दयाल सिंह (बिहार): मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं उपसभाध्यक्ष जो कि यह मंत्री महोदय का जो स्टेटमेंट आया है, इसकी अंग्रेजी और हिंदी कापी आप अपनी टेबिल पर मंगवाकर देख लीजिए। अंग्रेजी कॉपी इतनी साफ सुथरी है जैसेकि ब्रिटिश काल में "गेवरडीन" कपड़ा आता था और हिंदी की कापी ऐसी है कि उसे दूरबीन लगाने से भी कोई नहीं पढ़ सकता है। महोदय यह आप देख लीजिए। हमारा कहना है, अंग्रेजी को स्थिति कह रही है मानो सलमान खुर्शीद साहब का बढ़िया सूट हो और हिंदी बेचारी की स्थिति ऐसी है मानो कोटैया साहब का जो हैंडलूम है, वह रो रहा हो। दोनों में यह फर्क है इसलिए उपसभाध्यक्ष जी, मैं चाहूंगा कि हिंदी व अंग्रेजी, दोनों की प्रतियां जब भी सदन को टेबिल पर रखी जाएं तो दोनों की छपाई ऐसी हो कि कम से कम सदस्य उसे पढ़ लें, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। उपसभाध्यक्ष जी, यह बहुत गंभीर मुद्दा है।

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Sir, you direct the Government to

ensure that this is done in all the regional languages...(*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): I cannot decide that point. Mr. Virumbi, please take your seat...(*Interruptions*)

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: No, no. This type of tendency should be curbed...(*Interruptions*)

SHRI SHANKAR DAYAL SINGH: This is not a question of Hindi or English...(*Interruptions*).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGGARWAL): Mr. Virumbi is it necessary to raise controversial issues every time?...(*Interruptions*) Mr. Venkatraman, please take your seat...(*Interruptions*)

It is not a question of getting translations in various languages. It is a question of getting a good print. That is all. इस सम्बन्ध में प्रारंभ में जब यह मामला उठाया गया था तो अंग्रेजी की जो प्रति यहां वितरित की गई थी वह भी पढ़ने लायक नहीं थी और इसलिए आसन से यह व्यवस्था दी थी कि अच्छी प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाए। इसके बाद अंग्रेजी की अच्छी प्रतिलिपि सबको उपलब्ध हो गई है। हिन्दी की भी अच्छी प्रतिलिपि कराकर आपको उपलब्ध करा दी जाएगी।

श्री जी. वेंकट स्वामी : उपाध्यक्ष जी, आनरेबिल मैम्बर शंकर दयाल सिंह जी सुबह नहीं थे, जब वह सवाल उठा था इसके पहले भी। कम से कम अब तो हिन्दी में मिली है, सुबह तो मिली भी नहीं थी। अब यह जो मिली है तो कहा गया कि अच्छी नहीं मिली है। क्योंकि यह जल्दी में मिली है, कल तफसिया हुआ और वह करने में जरा देर हुई है। सुबह इसकी बात की ताइद की है। आइंदा जरूर अच्छी तहर से आइने की तरह साफ आपको मिलेगी।

श्री शंकर दयाल सिंह : मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। इनके जवाब से मैं संतुष्ट हूं और आशा करता हूं कि बुनकरों को इसी तरह आप सूत भी मुहैया करेंगे।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Mr. Md. Salim.

Mr. Md. Salim, just a minute.

Mrs. Margaret Alva, after this item is over, we are going to have a discussion on the Railway Budget and the Resolution. This is an important debate. The Railway Minister is not here. So, request you kindly to get him here to move the motion. If he is busy in the other House, I will permit him to go back, and any other Minister can deputise for him, but, I will not permit any other Minister to deputise for him so far as the moving of the Resolution is concerned. So, he has to be here at the initial stage to show respect to the House. Later on, I can permit him to go to the other House, but he has to be here when the discussion on the Railway Budget takes place. He can go back after five minutes, but, he has to be here. Otherwise, I will have no other option but to adjourn the House. So, I am warning you half-an-hour in advance.

श्री मोहम्मद सलीम (पश्चिमी बंगाल) : उपाध्यक्ष जी, पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने इस तरह से पहले ही सरकार को सचेत कर दिया, आधा घंटे पहले से। ऐसा होना ही चाहिए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): This is known as transparancy in dealings.

श्री मोहम्मद सलीम : इस तरह ट्रांसपेरेन्सी आपकी बातों में है या जिस तरह से आइने में है, अगर उस तरह से हेंडलम वीवर के मामले में हो जाती तो इतनी दिक्कत नहीं होती। यह जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा गया है और इसके बाद जो मंत्री जी का बयान आया है, इनसे यह पता चलता कि मंत्री जी जिस नजरिए से हेंडलूम वीवर के सवाल को देख रहे हैं और प्रागदा कोटैया जी से लेकर हम जैसे सदस्य तक जिस नजरिए से देख रहे हैं, दोनों एक जगह पर खड़े नहीं होते क्योंकि

जब ध्यानाकर्षण किया जा रहा है बुनकरों की समस्या को लेकर तो मंत्री जी अपना बयान शुरू करते हैं कि ऐसी कोई समस्या है ही नहीं यह बड़ी अफसोसनाक बात है। मैं समझता हूं कि यह जो ऊपर से देखने का सवाल है, तो नीचे तक उनकी नजर जाते जाते धुंधली हो जाती है और जो नीचे की समस्या है वह आप देख नहीं पाते हैं।

श्री जी० वेंकट स्वामी : मैं नीचे से आया हूं । . . (**व्यवधान**) . .

श्री मोहम्मद सलीम : इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। अगर ऊपर से आए हुए मंत्री होते तो मैं यह बात नहीं कहता। वेंकट स्वामी जी आप जैसे नीचे से आए हुए मंत्री से, नीचे के सवालों को लेकर लड़ने वाले और उसके साथ सीधा संपर्क रखने वाले दफ्तर में काम करने वाले वेंकट स्वामी जी से हमारी उम्मीद यह थी कि वह हेंडलूम वीवर का जो सवाल है उस पर आप मंत्री दफ्तर में बैठकर अफसरों के जरिए, चाहे राज्य सरकार के अफसर हो या केन्द्र सरकार के अफसर हों, ... आंकड़ा दिए हुए और उसके आधार पर अपना निर्णय लेकर, जरूरत पड़े तो थोड़ा उधार लेकर प्रागदा कोटैया जी से, उनकी नजर से देखने की कोशिश करते तो इस तरह का बयान नहीं आता।

श्री जी. वेंकटस्वामी : वह बयान क्या है जरा बताइए?

श्री मोहम्मद सलीम : मैं आ रहा हूं। आई हाइली आब्जेक्ट, यह सैकिंड लाइन में जो कहते हैं :—

"At the very outset, I would like to inform the House that there is no crisis in the handloom sector as raised by hon. Members of Parliament through their Calling Attention Notice."

तो फिर सारा दिन इस पर चर्चा करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। फिर अभी मंत्री जी जिस तरह से रिएक्ट किए, ये जवाब दे सकते थे, जवाब देने का उनका हक था, इससे यह पता चलता है कि इतने लोगों के इतना कहने के बाद, चाहे भोमानी जी कहें, चाहे जायसवाल जी कहें, सब पानी बहने के बाद गंगा गए, वे अभी भी उसी जगह पर खड़े हैं।

श्री जी. वेंकट स्वामी : अध्यक्ष जी, ऊपर और नीचे की बात करने पर मैंने कहा है कि मैं ग्रासरूट से आया हूं, ऊपर से नहीं आया हूं यह मैं आनरेबल मेम्बर को बताना चाहता हूं।

श्री मोहम्मद सलीम : मैं भाषण देने के लिए नहीं उठा था, मंत्री जी आप हमें प्रवोक कर रहे हैं, मैं कुछ मश्विरा देने के लिए उठा था। पहला मश्विरा यह है कि आप आंकड़े से बाहर आइए। आंकड़े में अगर आप यह कहते हैं कि यह सही है, हमारे हैंडलूम सेक्टर में कुछ डेवलपमेंट हुआ है, इसी रास्ते पर चलेंगे तो डेवलपमेंट कुछ होगा, आपका दफ्तर न होने पर भी होता, लेकिन सवाल यह है कि एक्सपोर्ट बढ़ा है प्रोडक्शन बढ़ा है इससे हमें यह अनुमान नहीं करना चाहिए कि हैंडलूम वीवर्स की जो कंडीशन्स हैं, उनमें सुधार आ गया है। ऊपर की तस्वीर और नीचे की तस्वीर में काफी अंतर होता है। हैंडलूम सैक्टर के बारे में जहां रेम्प में मांडल्स खादी पहनकर एग्जीबीशन करती है और एक्सपोर्ट हो या इन्वाइटी इम्पोर्टर्स हों जिनके सामने वह पेश किया जाता है फाइव स्टार होटल में कलर टी. वी. में उसकी तस्वीर देखते हैं उससे हम यह अंदाजा नहीं लगा सकते कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो बुनकरों के गांव हैं और वहां जो बच्चे हैं और वहां जो लोग पूरे परिवार को लेकर ठकाठक हैंडलूम चला रहे हैं उनकी स्थिति में सुधार आ गया है आपके आंकड़े में जरूर सुधार आया होगा। इसलिए आपकी कोशिश हमारी कोशिश इस सदन की कोशिश यह होनी चाहिए थी कि किस तरह से ओवर आल जो प्रोडक्शन में डेवलपमेंट आ रहा है हमारे जो अरनिंगस में डेवलपमेंट आ रहा है और हमारे जो एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं इसका फायदा हम नीचे तक किस तरह से

ले जाएं और इसी बारे में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आंकड़े जो आ रहे हैं और हकीकत जो है इसमें थोड़ा फर्क होता जा रहा है। इसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो मिडिलमेन हैं जो भी नाम से आप बोलें हम खुद देखते हैं। मैं सिर्फ वीवर्स और मास्टर वीवर्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं वहां से लकर के जो सूत धागा आदि लेकर के जो बेचते हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं जो मंत्रीजी के दफ्तर में आना-जाना करते हैं वीवर्स नहीं आते हैं मैं उन सबको लेकर के बोल रहा हूं तो बीच में जो मिडिलमेन हैं मिडिलमेन नहीं उन लोगों की स्थिति जरा सुधर रही है लेकिन हम फायदे को लाभ को किस तरह से बुनकर तक ले जाएं इसके लिए हम सबकी जिम्मेदारी है और हम सबकी कोशिश होनी चाहिए। एक जगह वह प्राइमरी सोसाइटी की बात किए हैं कि वीवर्स सोसाइटी को वह किस तरह से करेंगे लेकिन प्राइमरी से लेकर नेशनल लेबल तक आपके सरकारी दफ्तर से भी नहीं होगा और सिर्फ सोसाइटी से भी नहीं होगा सेमी गवर्नमेंटल हो सकता है तो ऐसा कुछ प्रबन्ध कीजिए आप कि किस प्रकार प्राइमरी यूनिट से लेकर के ऊपर तक आप थोड़ा डेमोक्रेटाइज कीजिए। जो बुनकर हैं, जो इस पेशे के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनका किस तरह से सीधा संबंध हो और उनको आप लाभ सीधा पहुंचाने की कोशिश करें।

दूसरी बात यह है कि जिस तरह से पूरे मुल्क में और मुल्क के बाहर जो हमारे हैंडलूम प्रोडक्टस हैं उसके मार्किट बढ़ रहे हैं हम यह नहीं कहते कि आप सब मामले में सब्सिडाइज्ड कर दो और पैसे दे दो लेकिन आप कुछ ऐसे वातावरण को तैयार कर सकते हैं जिसका लाभ उन बुनकरों को मिल सके। हमारी एक-एक जगह का एक-एक किस्म का एक प्रोडक्ट है और उसकी इंटरनेशनल मार्किट है उसके लिए हम ब्रांडनेम प्रमोट कर सकते हैं। केन्द्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, आपका डिपार्टमेंट हो, हम उस ब्रेंड नेम को अगर प्रमोट करते हैं तो उसके बाद जो भी वह स्टेंडर्ड मेनटेन करेंगे, वह सीधे उसको मार्किट कर सकते है, मिडिलमेन को एवॉयड कर सकते हैं। मिडिलमेन को अवाइड कर सकते हैं। चाहे वह विदेश में बेचें, चाहे वह सामान विदेश से ब्रांड नेम के नाम पर आए। हम अगर हिन्दुस्तानी चाय का ब्रांड नेम कर सकते हैं तो पूरे विश्व के बाजार में हिन्दुस्तानी हैंडलूम का ब्रांड नेम क्यों नहीं प्रमोट करते हैं?

यह बात सच है कि किस तरीके का कपड़ा बुनकर बनाते हैं, वह उनके वेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो यह प्रमोट करना चाहिए कि किस तरह से जो हायर वेज अर्निंग फैब्रिक्स है या हायर कॉस्ट वाले जो हैं, उस सैक्टर में हम शिफ्ट करें। वह गमछा बनाने वाले और टॉवल बनाने वालों से कम्पीट नहीं कर सकते। लेकिन उनकी जो स्कीम है उसको हम इंप्रूव कर सकते हैं, उसके डिजाईन को हम बढ़ा सकते हैं। उसके हम रिसर्च एंड डवलपमेंट का काम करेंगे। जहां भी यह सब सवाल आता है तो मंत्री जी कहते है कि हम ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप अब कब करेंगे? आजादी के पचास साल तो होने को चले हैं। तो पहले वह करना चाहिए था। इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि किस तरह से वह लो कॉस्ट फैब्रिक्स है, उससे वह शिफ्ट करें और उसमें हायर वेज अर्निंग जो अप मार्केट प्रोडक्ट्स है उसको वह किस तरह से बढ़ाएं। यह ट्रेनिंग हमको देनी चाहिए। उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है—चाहे वह कम्प्यूटर डिजाईन हों, चाहे वह ग्राफिक्स हों, चाहे वह ब्रांड नेम हों। अगर कम्प्यूटर लगाया जाए तो वह कौन करेगा? वह बुनकर नहीं कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि बुनकरों को डिपेंड करना पड़ता है, महाजन के पास, मास्टर वीवर्स के पास, बाजार के दुकानदारों के ऊपर। तो अर्निंग का जो मेजर पार्ट है, वह वे लोग ले जाते हैं जो हैंडलूम पर कभी बैठे नहीं हैं।

यह जो हैंक यार्न के सप्लाई के बारे में एक पेज का बयान दिया है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन हकीकत तो यह है कि हर सूत्र में हमें उस बात को उठाना पड़ता है। हमारे सदस्य जो सीधे बुनकरों से जुड़े हुए हैं, वह अक्सर यह बोलते रहते है और अभी जायसवाल जी भी बोल हैं। जो उनको सूत मिलता है उससे 15 दिन से ज्यादा का काम उनको नहीं मिल पाता हैं। तो फिर हम प्रोडक्टिविटी क्या बढ़ाएंगे?

दूसरी बात, जो यह वर्क शैडकम-हाऊसिंग स्कीम है, यह समाज का मामला है, उनके परिवार का मामला है। इसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह तमाम बातें जो हम कर रहे हैं, मौडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं या आप मार्केट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, वह होगा नहीं अगर हम उन बुनकरों के परिवारों को शिक्षित नहीं करेंगे, उनके बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे हर जगह आप देखेंगे, चाहे वह बीड़ी के मजदूर हों चाहे, वह बुनकर हो, उनका घर, उनके बैठने की जगह, उनके सोने की जगह, काम करने की जगह सभी एक जैसी होती हैं। तो यह जो स्कीम है, उसको आप सही ढंग से लागू करिए। इस स्कीम को अगर आप एक-एक गांव लेकर लागू करेंगे, जहां उसका अपना घर अलहदा हो और काम करने की जगह अलहदा हो तो उसके परिवार के बच्चे कम से कम पढ़ तो सकेंगे। गांव से जब हम गुजरते हैं तो वहां से ठकाठक-ठकाठक आवाज आती है। तो ऐसे कभी बीबी करती है, कभी शौहर कहता है और कभी उसके बच्चे करते हैं। तो फिर वहां बच्चे पढ़ेंगे कब? तो जो काम करने की शैड स्कीम है, उसको बढ़ाना चाहिए और उसके रहने की स्थिति में सुधार लाना चाहिए।

मैं आपके बयान के पेज-4 पर [illegible] ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। "The Government is also going to assist the weavers to sell their products through district level fairs and exhibitions." आपका ध्यान चाहूंगा। "The Government is also going to assist the weavers to sell their products through district level fairs and exhibitions."

आप कब करेंगे? अब आप करने जा रहे हैं। आपको यही करवाना पड़ेगा कि जो वीवर्स हैं उनको अपना प्रोजेक्ट चाहे कस्टमर्स हों या इंपोर्टर्स हों, उनको डायरेक्ट देना पड़ेगा और तभी जो मिडिलमैन का मामला है, वह हट जाएगा। इस बारे में आप करने जा रहे हैं, ऐसा बयान देने से नहीं होगा। आप यहां बताइए, टाईम लिमिट दीजिए कि यह कब तक होगा? आप प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, उसका आप कितना परसेंट कवर करेंगे? पासपोर्ट की बात कर रहे हैं, कितना परसेंट आप कवर करेंगे? जो डायरेक्ट वीवर्स को ऐक्सेस मिलेगा, वह आकर के मार्केट में अपनी सेल को कर पाएंगे। और अगर आप इजाजत दें तो और भी कह सकता हूं लेकिन मैं अपनी बात को खत्म करूंगा इस बात से कि आप अपनी नजर को, फिर मैं दोहराऊंगा, आंकड़ों से हटा करके चेहरे पर देखें। जो बुनकर इस मुल्क का है, वह आप ही का है, आप उन्हीं में से हैं, आप में से वह हैं। उनके चेहरे पर आप अगर पढ़ेंगे तो आपके ऐक्सपोर्ट अर्निंग्स के दो फिगर्स हैं, उसके चेहरे पर लिखे हुए नहीं हैं। इसलिए मैं आपसे फिर दरखास्त करूंगा कि कम से कम अपने जवाब में इस बात को कहें और इसे तसलीम करें कि हैंडलूम वीवर्स का क्राइसिस है, संकट है। जिस अफसर ने लिख दिया है कि संकट नहीं है, वह सही नहीं है, गलत है।

†[ ] مشری محمد سلیم بنگالی: اپ سبھا ادھیکش - پہلے تو آپکو دھنیواد دینا ہوں گا کہ آپنے اس طرح سے پہلے ہی سرکار کو سچیت کر دیا آدھا کھیلنا پہلے سے ایسا ہونا ہی چاہیئے۔

THE VICE-CHAIRMAN: This is known as transparancy in dealings.

مشری محمد سلیم اسطرح شراسینسی آپکی باتوں میں ہے یا جسطرح آپنے کہا ہے۔ اگر اس طرح سے ہینڈلوم ویورس کے معاملے میں ہو جاتی تو اتنی دقت نہیں ہوتی۔ یہ جو دھیان آکرشن پرستاو اٹھایا گیا ہے اور اسکے بعد جو منتری جی کا جو بیان آیا ہے۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ منتری جی جس نظر یئے سے ہینڈلوم ویورس کے سوال کو دیکھ رہے ہیں۔ اور میرا خیال تو یا جی سے کیلر ہم جیسے ساتھی

†[ ] Transliteration in Arabic script.

پر اپنا بیان تو نہیں لیکن ضرورت پڑے
تو مختصر اً اوھاد لیکر پر اپنا بیان
ملی نظر سے دیکھنے کی کوشش کرتے تو اصل
بیان نہیں آتا۔

شری جی۔ ونکٹ سوامی: وہ بیان
ہے ذرا بتا دیں۔

شری محمد سلیم: میں آدھا ہوں۔
تی وائی ایس ایجنسی۔ یہ سیکنڈ لائن
جو کہتے ہیں۔]

"At the very outset, I would like t
inform the House that there is n
crisis in the handloom sector a
raised by hon. Members of Parli
ment through their calling attentio
Notice."

†[تو پھر سارا دن اس پر چرچا
کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی
پھر بھی منتری جی جس طرح سے وہ انفارمیشن
دے سکتے تھے۔ وہ جواب
دینے کا ان کا حق تھا۔ اس سے یہ پتا چلتا
ہے۔ کہ اتنے لوگوں کے اٹھنے کے بعد
پانی ہے۔ نعمانی جی نہیں۔ چاہے جسونت
جی نہیں۔ سب پانی پینے کے بعد لٹکا
لے۔ وہ ابھی ابھی اس جگہ پر کھڑے
ہوئے ہیں۔

شری جی۔ ونکٹ سوامی: ادھیکش
مہاشیہ اور نیچے کی بات کرتے ہوئے میں نے
کہا کہ گراس روٹ سے آیا ہوں اور میرے
پاس زمینی سے ڈیٹا ہے۔ دونوں
ایک جگہ پر کھڑے نہیں ہوتے۔ کیونکہ
جب وہاں آندولن چلایا جا رہا ہے۔
ہینڈلوم کی سمسیا کو لیکر نو منتری جی
اپنا بیان شروع کرتے ہیں کہ ایسی کوئی
سمسیا ہے بھی نہیں۔ یہ بڑی افسوسناک
بات ہے۔ سمجھتا ہوں کہ یہ اوپر
سے دیکھنے کا سوال ہے۔ تو نیچے تک
آنکھ نظر جاتے جاتے دھندلی ہو جاتی ہے۔
اور جو نیچے کی سمسیا ہے وہ آپ دیکھ
نہیں پاتے ہیں۔

شری جی۔ ونکٹ سوامی: میں نیچے
سے آیا ہوں۔ "مداخلت"۔۔۔

شری محمد سلیم: اسلئے میں آپکو کہہ
رہا ہوں۔ اگر اوپر سے آئے ہوئے منتری
ہوتے تو میں یہ بات نہیں کہتا۔ ونکٹ
سوامی سے آپ نیچے سے اوپر گئے ہوئے
منتری سے۔ نیچے کے سوالوں کو لیکر لڑنے
والے اور اسکے ساتھ سیدھا سندھ رکھنے
والے دفتر میں کام کرنے والے ونکٹ
سوامی جی سے ہماری امید یہ تھی کہ
وہ پہلے نوم دور کا سوال ہے اس
پر آپ منتری کے دفتر میں بیٹھکر
افسروں کے ذریعے۔ چاہے راجیہ سرکار
کے افسر ہوں یا کندر سرکار کے افسر ہوں
آنکڑہ دیئے ہوئے اور اسکے آدھار

†[]Transliteration in Arabic Script.

ہینڈلوم چلا رہے ہیں - انکی اسسٹنس میں
مدھار آیا ہے - آپکے انکڑے میں ضرور
مدھار آنا چاہیئے گا - اسلئے آپکی کوشش
ہماری کوشش اس سمت کی کوشش یہ
ہونی چاہیئے تھی کہ کھیت سے اور ان
جو پروڈکشن میں ڈیولپمنٹ ادھار
ہمارے جو اوٹلس میں ڈیولپمنٹ
آدھا ہے - اور ہمارے جو ایکسپورٹ
بڑھ رہے ہیں اسکا فائدہ ہم نیچے تک
کھیت سے لے جائیں اور اسی بارے میں
اپکا دھیان دلانا چاہتا ہوں کہ انکڑے
جو آدھے ہیں اور حقیقت جو ہے - اسمیں
تھوڑا فرق ہوتا جارہا ہے - اسکے لئے
سب سے بڑی دقت یہ ہے کہ جو مڈل مین
ہے - جو بھی نام سے آپ بولیں - ہم خود
دیکھتے ہیں - میں صرف ریورس کی اور
ماسٹر ویورس کے بارے میں بات نہیں کررہا
ہوں دھان سے لیکر کے جو سوت دھاگا
اپنی لیکر کے جو بیچتے ہیں - جو ایکسپورٹ
کرتے ہیں - جو منتری جی کے دفتر میں
آنا جانا کرتے ہیں - وہ ریورس نہیں آتے
ہیں - میں ان سیکٹر لیکر کے بول رہا ہوں
تو بیچ میں جو مڈل مین ہے - مڈل مین
نہیں - ان لوگوں کی اسسٹنس ذرا سدھری
ہے - لیکن ہم فائدے کو - لاسٹ تو سرچ

ہیں آیا ہوں - یہ میں انٹرمیڈیل ممبر کو بتانا
چاہتا ہوں -

شری محمد سلیم : میں جانکاری دینے کیلئے
نہیں اٹھا تھا - منتری جی آپ ہم پر بوجھ
کررہے ہیں - میں کچھ مشورہ دینے کیلئے
اٹھا تھا - پہلا مشورہ یہ ہے کہ آپ انکڑے
سے ہاتھ دھوئیے - انکڑے میں اگر آپ یہ کہتے
ہیں کہ یہ صحیح ہے ہمارے ہینڈلوم سیکٹر میں
کچھ ڈیولپمنٹ ہوا ہے - اس واسطے
پرچیزیں گے تو ڈیولپمنٹ کچھ ہوگا -
آپکا دھیان نہ ہوگا میں بھی ہوتا لیکن یہ ہے
کہ ایکسپورٹ بڑھا ہے - پروڈکشن بڑھا
ہے - اس سے ہمیں یہ انومان نہیں کرنا چاہیئے
کہ ہینڈلوم ورکر کی جو کنڈیشن ہے -
اسمیں سدھار اچھا ہے - اوپر کی تصویر
اور نیچے کی تصویر میں کافی انتر ہوتا ہے -
ہینڈلوم سیکٹر کے بارے میں جہاں دیہ
میں ماڈرن کھادی پینکلر انگلی بیان کرتی
ہے اور ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے وہ بھی ہو چکے
سامنے وہ پیش کیا جاتا ہے - مائیکرو اسکوپ
یونٹ میں کلوتی - وہ میں انکی تصویر
دیکھتے ہیں - اس سے ہم یہ اندازہ نہیں لگا
سکتے کہ پوری انٹرپریٹیشن میں جو بنکروں کے
گاؤں ہیں اور وہاں جو بچے ہیں اور وہاں
جو لوگ پورے پریوار کو لیکر بھوکا بھٹک

†[] Transliteration in Arabic script.

سرکار ہو۔ راجیو سرکار ہو۔ آپکا
ڈیپارٹمنٹ ہو۔ ہم اس ہینڈلوم کو اگر
پروموٹ کرتے ہیں تو اسکے بعد جو بھی وہ
اسٹینڈرڈ ڈیفینس کرینگے۔ وہ بعد کے
اسکو مارکیٹ کر سکتے ہیں۔ مڈل مین کو ایلیمینیٹ
کر سکتے ہیں۔ چاہے وہ ریشن میں بیچے جائے
وہ ہمارا ریشن سسٹم کے نام پر
آئے۔ ہم اگر ہندوستانی چائے کا برانڈ نیم کر
سکتے ہیں۔ تو پولینڈ و نیو کے بازار میں
ہندوستانی ہینڈلوم کا برانڈ کیوں نہیں
پروموٹ کرتے ہیں۔

یہ بات سچ ہے کہ کس طریقے کا کپڑا انکو
بناتے ہیں۔ وہ انکے دام کے اور پرچیز کرتا ہے
تو یہ پروموٹ کرنا چاہیے کہ اسٹیج سے جو
ڈائریکٹر ویو اور سکرپٹ فیسلس ہے یا فائر کاسٹ والے
جو ہیں۔ ان سیکٹر میں ہم سفٹ کریں۔ وہ

وہ کپڑا بنانے والے اور ٹاول بنانے والوں سے
کمیٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن انکی جو اسکیل ہے۔
اسکو ہم امپروو کر سکتے ہیں۔ انکے ڈیزائن
کو ہم بڑھا سکتے ہیں انکے ہم اسٹرچ ایڈڈ
ڈیولپمنٹ کا کام کرینگے۔ جہاں بھی یہ سب
سوال آتا ہے تو منسٹری جی کہتے ہیں کہ ہم ایسا
کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اب کب
کرینگے۔ آزادی کے پچاس سال تو ہونے کو
چلے ہیں۔ تو پہلے تو وہ کرنا چاہیے تھا۔ انکی

سے بنکر تک لے جائیں انکے لیے ہم سبسڈی
فراہم کریں۔ اور ہم سبکی کوشش ہونی
چاہیے کہ۔ ایک جگہ وہ ہیلوٹ سوسائٹی
کی بات کہتے ہیں کہ ہینڈلوم ہیلوٹ سوسائٹی کو وہ
دو کلرج سے کریں گے۔ لیکن ہیلوٹ سے لیکر
فینشل لیول تک۔ اپکے سرکار دفتر سے بچ
نہیں ہوگا۔ اور صرف سوسائٹی سے بچ
نہیں چلیگا۔ سبکی کوپریشن ہوگا۔ تو
ایسا کچھ پیرامیٹرز کیجیے آپ کہ کس
پیرامیٹر ہیلوٹ یونٹ سے لیکر اوپر تک
آپ تھوڑا ڈیفرینشیٹ کیجیے۔ جو بنکر
ہیں جو اس پیشے کے ساتھ جڑے ہوئے
ہوئے لوگ ہیں۔ انکا کلرج سے سیدھا
سپورٹ ہو اور انکے انکو آپ لابھ سیدھا
پہونچانے کی کوشش کریں۔

دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ
ہمارے ملک میں اور ملک کے باہر جو ہماری

ہینڈلوم پروڈکشن ہیں انکے مارکیٹ بڑھ
رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ سبھی معاملے
میں سبسیڈائز کریں اور پیسے دیں لیکن
آپ کچھ ایسے دانا دون کو نیاد کر سکتے ہیں
جسکا لابھ ان بنکروں کو مل سکے۔ ہماری ایک
ایک جگہ کا۔ ایک ایک قسم کا ایک پروڈکٹ
ہے اور اسکی انٹرنیشنل مارکیٹ ہے۔ انکے
ہم برینڈ نیم پروموٹ کر سکتے ہیں۔ کینیڈا

اگر شت کرنا چاہتا ہوں یہ تمام باتیں جو ہم کر رہے ہیں - ماڈرنائزیشن کی بات کر رہے ہیں - یا آپ مارکیٹ بروڈکیٹ کی بات کر رہے ہیں - وہ ہو نہیں - اگر ہم ان بنکروں کے پیداواروں کو تکسٹ نہیں کرینگے انکے بچوں کو شکشا نہیں دینگے - ہر جگہ آپ دیکھینگے - چاہے وہ بیڑی مزدور ہوں - چاہے وہ بنکر ہوں - انکا گھر انکے بیٹھنے کی جگہ انکے سونے کی جگہ کام کرنے کی جگہ سبھی ایک جیسی ہوتی ہیں - تو یہ جو اسکیم ہے - اسکو آپ صحیح ڈھنگ سے لاگو کریں - اس سکیم کو اگر آپ ایک ایک گاؤں میں لاگو کرینگے - جہاں انکا اپنا گھر علیحدہ ہو اور کام کرنے کی جگہ علیحدہ ہو تو انکے بچے کم سے کم پڑھ سکیں گے - گاؤں سے جب ہم گذرتے ہیں تو وہاں سے کھٹا کھٹ کی آواز آتی ہے - تو ایسا کہیں ہوتی ہے - کہیں شور ہوتا ہے - اور کہیں انکے بچے کرتے ہیں - تو پھر وہاں بچے پڑھینگے کب - تو جو کام کرنے کی جگہ اسکیم ہے - اسکو بڑھانا چاہیے اور انکے رہنے کی بستی میں سدھار لانا چاہیے -

†[ ] Transliteration in Arabic script.

شریننگ ہونی چاہیے کہ کس طرح سے وہ نو کامرشل فیبرک بنا سکتے ہیں - اس سے وہ سیکھ کریں اور اسی طرح سے لوننگا جو اب مارکیٹ بروڈکشن میں انکو وہ اسطرح سے بڑھاوا دیں یہ شریننگ ہم کو دینی چاہیے - اسکے لئے جو رکاوٹ ہے - چاہے وہ کاپر کمپوزر ہیں - چاہے وہ گراکلس ہوں - چاہے وہ برانڈ نیم ہوں - اگر کمپوزر لگایا جائے تو وہ کوئی بھی بنکر نہیں کر سکتے ہیں - لیکن وقت یہ ہے کہ بنکروں کو پینڈ کرنا پڑتا ہے - ہماچل کے پاس - مالوہ ورندیل کے پاس - بازار کے دکانداروں کے اوپر تو نو منکھ کا جو بیج بارت ہے - وہ لوگ لے جاتے ہیں نہ جو ہینڈ لوم پر کمپوزر بیٹھے نہیں ہیں - یہ جو ہینڈ لوم کے پیداوار کے بارے میں آپکا ایک بیج کا بیان دیا ہے میں اسمیں نہیں جاؤنگا لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ہر ستر میں اس بات کو اٹھانا پڑتا ہے - ہمارے سدھ سے جو سیدھے بنکروں سے جڑے ہوئے ہیں - وہ اگر یہ بولتے رہتے ہیں - اور ابھی جیسا ان بولے ہیں - جو انکو سوت ملتا ہے اس ۱۵ دن سے زیادہ کا کام انکو نہیں مل پاتا ہے - تو پھر ہم پروڈکشن وغیرہ کیا بڑھائینگے - دوسری بات جو یہ ورک شیڈ کم ماڈرنائز اسکیم ہے - یہ سماج کا معاملہ ہے - انکے ہر ہر کا معاملہ ہے - اسکی طرف آپکا دھیان

†[ ] Transliteration in Arabic script.

میں آپکے بیان کے بیچ — براہ کرپا دھیان
آکرشت کرنا چاہتا ہوں۔]

"The Government is also going to assist the weavers to sell their products through district level fairs and exhibitions."

"The Government is also going to assist the weavers to sell their products through district level fairs and exhibitions."

† [ایک کلب کریں گے۔ اب آپ کرنے جا رہے ہیں۔ آپکو یہیں کروانا پڑیگا کہ جو ڈسٹرکٹ لیول ہیں انکو اپنا پروڈکٹ چاہیے وہ ڈسٹرکٹ لیول ہوں یا اسٹیٹ لیول ہوں انکو ڈائریکٹ کرنا پڑیگا۔ اور جبھی جو مڈل مین کا معاملہ ہے وہ ہٹ جائیگا۔ اس بارے میں آپ کرنے جا رہے ہیں۔ ایسا بیان دینے سے نہیں ہوگا۔ آپ بیان بتا دیجئے۔ تاکہ ہم لمیٹ دیجئے۔ کہ یہ کب تک ہوگا۔ آپ پروڈکشن کی بات کر رہے ہیں اسکا آپ کتنا پرسنٹ کور کریں گے۔ ایکسپورٹ کی بات کر رہے ہیں۔ کتنا پرسنٹ آپ کور کریں گے۔ جو ڈائریکٹ ورکرس کو ایکسپورٹ ملیگا۔ وہ اگر کے مارکیٹ میں اپنی مال کو کر پائینگے۔ اور اگر آپ اجازت دیں تو اور بھی کہہ

†[]Transliteration in Arabic Script.

سکتا ہوں لیکن میں اپنی بات کو ختم کرونگا اس بات سے کہ آپ اپنی قلم کو۔ پھر میں دوہراؤنگا ایکڈوں سے بنا کر کے چمڑے پر دیکھیں۔ جو ہنر اس ملک کا ہے۔ وہ آپ ہی کا ہے۔ آپ انہیں سے ہیں۔ آپ میں سے وہ ہیں۔ انکے چہرے اگر آپ پڑھینگے تو ایکسپوزیٹ اوننگس کے جو فیچرس ہیں انکے چہرے پر کھلے ہوئے دکھتے ہیں۔ اسلئے میں آپ سے پھر درخواست کرونگا کہ کم سے کم اپنے جواب میں اس بات کو کہیں اور اسے تسلیم کریں کہ ہینڈلوم سیکٹر کی کانٹریبیوشن ہے۔ سینکڑے ہے جس افسر نے لکھ دیا ہے کہ سینکڑے نہیں ہے۔ وہ صحیح نہیں ہے۔ غلط ہے۔]

श्री जलालुद्दीन अंसारी (बिहार) : दो सवालों पर मैं स्पष्टीकरण चाहता था। इसकी इजाजत दीजिए। सिर्फ स्पष्टीकरण।

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल) : दो सवाल ? बोलिए।

श्री जलालुद्दीन अंसारी : पहला सवाल है उपसभाध्यक्ष महोदय कि बुनकरों की जो स्थिति है, बहुत ही खराब है। खास करके जो हैंडलूम वर्कर्स हैं और उनके सुधार के लिए माननीय मंत्री जी ने बहुत सारे सुझाव दिए हैं और कहा है कि अमुक-अमुक कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि उनकी अवस्था में अगर कोई तुरंत सुधार की बात करनी है तो अभी हमारे जायसवाल जी ने कहा कि पंद्रह दिन के लिए उनको सूत मिला है। मैं जानता हूं कि बिहार में बहुत सारे बुनकर हैं जिनको महीने में एकसप्ताह के लिए भी सूत उपलब्ध नहीं होता है। मैं जानना चाहता हूं कि सचमुच अगर करघा बुनकरों के हालात में सुधार लाना चाहते हैं

मंत्री जी तो उन बुनकरों को नियमित रूप से सूत देने की व्यवस्था वे करते हैं या नहीं और इस नियमित आपूर्ति के लिए इसके पास कोई योजना पूरे देश भर में है या नहीं या इस संबंध में कोई कदम उठाना चाहते हैं या नहीं ?

दूसरी बात, कि जो भी वे मोटा कपड़ा बनाते हैं उसको आम लोग खरीदना नहीं चाहते, यहां तक कि गरीब भी खरीदना नहीं चाहते। अगर उन बुनकरों को सचमुच राहत देना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि हर जगह, पूरे देश के हर सेंटर में अगर उनके कपड़े खरीदने का केन्द्र बनाते हैं तभी उनकी स्थिति में सुधार हो सकता है। ये तो कपड़ा लेकर दौड़ते रहते हैं, उस तरह का मोटा कपड़ा कोई आज खरीदने को तैयार नहीं है। उससे अच्छा हैंडलूम में और दूसरी जगह मिल जाता है। इसलिए हम जानना चाहेंगे कि अगर सचमुच उनके लिए बाजार की व्यवस्था वे नहीं करते हैं तो एक यह सुझाव तो आया ही है कि बाजार की मांग के मुताबिक उनको डिजाइन दिए जाएं। लेकिन उनकी खरीद की अगर व्यवस्था नहीं होगी तो हम समझते हैं कि उनकी स्थिति में कोई सुधार होने वाला नहीं है चाहे यह सरकार और मंत्री जी का दावा लाख क्यों न हो।

तीसरी बात, यह जो बुनकर कोऑपरेटिव है, मेरी जो जानकारी है, और यह कारपोरेशन, अब वेस्टेड इंटरेस्ट का केन्द्र बन गए हैं। माफ करें, इसलिए ऐसी कोऑपरेटिव को पुनर्गठित करने का, री-ऑर्गेनाइज करने का, उनको डेमोक्रेटिक तरीके से चलाने और उनके द्वारा जो सुविधाएं बुनकरों को मिलती हैं, वह मिलें। इसकी निगरानी अगर नहीं होती है तो यह कोऑपरेटिव और निगम, दोनों उनके शोषण का केन्द्र बन गए हैं और निहित स्वार्थों का अड्डा बन गए हैं। हम समझते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई और उनमें सुधार की दिशा में कदम उठाया जाना चाहिए।

†[श्री जलाल उद्दीन अंसारी : दो सवालों पर मैं सप्लीमेंट्री जानना चाहता। उनकी अनुमति दीजिये। सिर्फ सप्लीमेंट्री। आप समझा दीजिये। श्री सतीश अग्रवाल : दो सवाल पूछिये।

श्री जलाल उद्दीन अंसारी : पहला सवाल है आप समझा दीजिये। मेरे कई बुनकरों की जो इंस्पेक्शन है बहुत ही खराब है। खासकर के जो हैंडलूम वर्कर्स हैं और उनके सहकार के लिये माननीय मंत्री जी ने बहुत सारे समझौते किये हैं। और कहा है कि एक एक कदम उठाये जा रहे हैं। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि उनकी इंस्पेक्शन के बारे में अगर कोई नोट सहकार की बात करनी है तो अभी हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा कि पन्द्रह दिन के लिये उनको सूत मिलता है। मैं जानना चाहता हूं कि बिहार में बहुत सारे बुनकर हैं। जिनको महीने में एक सप्ताह के लिये भी सूत एलॉट एलॉटमेंट नहीं होता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि सच सच अगर करना है बुनकरों की हालत में सुधार लाना चाहते हैं। तो मंत्री जी तो उन बुनकरों को नियमित रूप से सूत देने की व्यवस्था वे करते हैं या नहीं और इस नियमित आपूर्ति के लिए इसके पास कोई योजना पूरे देश भर में है या नहीं या इस संबंध में कोई कदम उठाना चाहते हैं या नहीं ?

दूसरी बात, कि जो भी वे मोटा कपड़ा बनाते हैं उसको आम लोग खरीदना नहीं चाहते, यहां तक कि गरीब भी खरीदना नहीं चाहते। अगर उन बुनकरों को सचमुच राहत देना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि हर जगह, पूरे देश के हर सेंटर में अगर उनके कपड़े खरीदने का केन्द्र बनाते हैं तभी उनकी स्थिति में सुधार हो सकता है। ये तो कपड़ा लेकर दौड़ते रहते हैं, उस तरह का मोटा कपड़ा कोई आज खरीदने को तैयार नहीं है। उससे अच्छा हैंडलूम में और दूसरी जगह मिल जाता है। इसलिए हम जानना चाहेंगे कि अगर सचमुच उनके लिए बाजार की व्यवस्था वे नहीं करते हैं तो एक यह सुझाव तो आया ही है कि बाजार की मांग के मुताबिक उनको डिजाइन दिए जाएं। लेकिन उनकी खरीद की अगर व्यवस्था नहीं होगी तो हम समझते हैं कि उनकी स्थिति में कोई सुधार होने वाला नहीं है चाहे यह सरकार और मंत्री जी का दावा लाख क्यों न हो।

तीसरी बात, यह जो बुनकर कोऑपरेटिव है, मेरी जो जानकारी है, और यह कारपोरेशन, अब वेस्टेड इंटरेस्ट का केन्द्र बन गए हैं। माफ करें, इसलिए ऐसी कोऑपरेटिव को पुनर्गठित करने का, री-ऑर्गेनाइज करने का, उनको डेमोक्रेटिक तरीके से चलाने और उनके द्वारा जो सुविधाएं बुनकरों को मिलती हैं, वह मिलें। इसकी निगरानी अगर नहीं होती है तो यह कोऑपरेटिव और निगम, दोनों उनके शोषण का केन्द्र बन गए हैं और निहित स्वार्थों का अड्डा बन गए हैं। हम समझते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई और उनमें सुधार की दिशा में कदम उठाया जाना चाहिए।

بن گئے ہیں - اور بہت سے ورکرز تعون کا اڑا بن گئے ہیں - ہم سمجھتے ہیں انکے خلاف کارروائی اور ان میں سدھار کی دشا میں قدم اٹھایا جانا چاہیے اور جن تانتری طریقے سے -

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल) : मंत्री महोदय कृपया स्पष्टीकरण दे दें आप। कितने, 15 मिनट लगेंगे ?

श्री जी० वेंकटस्वामी : आप जितने मिनट कहें। एक घंटा भी बोल सकता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल) : मैंने इसलिए कहा कि सदन की इच्छा के अनुरूप रेल मंत्री महोदय आ चुके हैं और उनको वापस लोक सभा जाना है इसलिए, अन्यथा तो ज्यादा देर तक बोल सकते थे लेकिन 10-15 मिनट में समाप्त कर दें।

श्री जी० वेंकटस्वामी : जैसा आप कहें।

श्री जी. वेंकट स्वामी : उपसभाध्यक्ष जी, यह एक बड़ा गम्भीर मसला है। **(व्यवधान)**

SHRI PRAGADA KOTAIAH: Sir, I want to make one submission only. He has referred to several things in the statement but what we want is that the supply of yarn to handloom weavers is made for fifteen days in a month.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): You have made that point sufficiently.

SHRI PRAGADA KOTAIAH: All the schemes are not implemented.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): You hear the reply first, Mr. Kotaiah.

श्री जी० वेंकटस्वामी : उपसभाध्यक्ष जी, मैं जानता हूं प्रागदा कोटैया जी ने जो कालिंग अटेंशन नोटिस दिया है, इसके बारे में पूरा हाऊस जानता है और सारे आनरेबल मैम्बर इसमें दिलचस्पी रखते हैं। मैं हाऊस को आपके जरिये यह बताना चाहता हूं कि यह देश का बड़ा गम्भीर मसला है। जैसे ही

کو صحیح صحیح واقعات دینا چاہتے ہیں تو میرا سجھاؤ یہ ہے کہ ہر جگہ - پورے دیش کے ہوسٹنگ میں اگر کپڑے خریدنے کا کیندر یہ بنانے ہیں تبھی انکی اسسٹنٹ میں سدھار ہوگا

یہ تو کپڑا الگ دوکانے رہتے ہیں - اسلئے کا موٹا کپڑا کوئی آج خریدنے کیلئے تیار نہیں ہے - اس نے اچھا ہینڈ لوم میں اور دوسری جگہ ملتا ہے - اسلئے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اگر صحیح بیچ انکے لئے بازار کی ویوستھا وہ نہیں کرتے تو ایک یہ سجھاؤ تو آیا ہیں ہے کہ بازار کی مانگ کے مطابق انکو ڈیزائن دیئے جائیں - لیکن انکی خریدکی اگر ویوستھا نہیں ہوگی تو ہم سمجھتے ہیں کہ انکی اسسٹنٹ میں کوئی سدھار ہونے والا نہیں ہے - چاہیے یہ سرکار کا اور منتری جی کا دیکھ الگ کیوں نہ ہو -

دوسری بات - یہ جو ہنکر ہیں انڈسٹریز ہے - میری جو جانکاری ہے اور یہ کاٹیج انڈسٹریز ہے اور یہ کاٹیج انڈسٹریز ہیں اب ویسٹیج انٹرسٹ کا گیندر بن گئے ہیں - معاف کریں گے - اسلئے اس کو پریمیٹو اور نگم دونوں بند کرنے کا - ڈی ریگولیٹ کرنے کا - انکو ڈیریگولیٹ کرنے سے چلانے کیلئے اور انکے دوار جو سوید ہانیکر ہنکروں کو ملتی وہ ملیں - اسکی نگرانی اگر نہیں ہوتی ہے تو یہ کارپوریشنز اور نگم دونوں انکے منسٹر شن کا کیندر

मैंने चार्ज लिया सारे हिन्दुस्तान के वीवर्ज की क्या मुश्कलात हैं, उनको जानने की कोशिश मैंने की। एक्चुअल उनका जो लिविंग बहुत बुरी हालत में था और आज भी है। मैं यह नहीं कहता हूं कि उनकी हालत पूरी तरह से सुधर गई है। उसको किस तरह से सुधारा जाए, एक करोड़ से ऊपर की वीवर्ज की पापुलेशन है, इस पूरी कम्युनिटी का दुख दूर करने के लिए, उनको सही मायनों में क्या चाहिये, वह मैंने सब से पहले जानने की कोशिश की। उन लोगों ने पहला क्वेश्चन यही किया कि साहब आपकी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट मिल कर हम को हैंक यार्न सप्लाई नहीं करते। अगर उसकी सप्लाई हमें बराबर की जाए तो हम कपड़ा बुन सकते हैं और बेच सकते हैं, कपड़ा बेच कर जिन्दा रह सकते हैं। कम से कम पावर्टी लाइन से ऊपर आने की कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद से सेवंथ फाइव ईयर प्लान में टोटल वीवर्स के वेलफेयर के लिए और उनकी जो कारकर्दगी है वीवर्स की मदद करने के लिए लगभग 11 सौ करोड़ रुपया था जिसमें प्लान में 131 करोड़ रुपया था मुझे यह देख कर ताज्जुब हुआ कि इतनी छोटी सी रकम में किस तरह से इतने करोड़ लोगों का हम भला कैसे कर सकते है। मैंने स्कीम बनाई। मैं आनरेबल मेम्बर्ज को यह बता देना चाहता हूं कि रूरल डवलपमेंट के तहत भी जो इसके अन्दर कुछ पैसा आना चाहिये, मैं जड़ के अन्दर गया और यह देखा कि कई वीवर्ज ऐसे हैं जिनके पास हथकरघा नहीं है। वह क्या कर सकते हैं? उनके बच्चे बेरोजगार हैं जो काम नहीं सीख सके हैं, उनके लिए क्या करना चाहिये, उनको मकान चाहिये, उनको वर्क शेड चाहिये। इस तरह से कई चीजें हमने रूरल डवलपमेंट से हासिल की जिसमें राज्य सरकारों, बैंकों एवं केन्द्रीय सरकार के अनुदान मिलाकर 682 करोड़ रुपये का हमने रूरल डवलपमेंट में प्रावधान कराया। 3,27,000 हथकरघे उन लोगों को देने के लिए आई०आर०डी०पी० में प्रावधान करवाया ताकि जिसके पास लूम नहीं है उसको लूम मिल सके और आई० आर०डी०पी० के तहत अपना काम शुरू कर सके। एक लाख बुनकरों को देश में बेरोजगारी से बचाने के लिए, उनकी ट्रेनिंग का भी हमने प्रबन्ध किया है। "ट्राइसेम" के तहत उनको ट्रेनिंग दिलवाई जा रही है कि किस तरह से वीविंग कर सकते हैं। हाऊस-कम-वर्क शेड की स्कीम को लागू किया। इन्दिरा आवास योजना के तहत लोगों के लिए मकान बनाने का काम किया। करोड़ों रुपया रूरल डवलपमेंट मद से पैसा खर्च करके उनके स्टैंडर्ड आफ लिविंग को ऊपर लाने की कोशिश की। मैं हाऊस को यह बताना चाहता हूं कि काम शुरू हो गया है। यह मैं मानता हूं स्टेट गवर्नमेंट्स को जिस तेजी के साथ आगे आना चाहिये, उस तेजी से काम नहीं हो रहा है। उनका पीछा मैं कर रहा हूं। इतना ही नहीं, जैसे मैंने पहले बताया था, अभी आनरेबल मैम्बर्ज भी बोल रहे थे कि उनको हैंक यार्न सप्लाई किया जाना चाहिये। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ ओब्लीगेशन आफ हैंक यार्न का कि यह क्यों अमल में नहीं आ रहा है, अमल में आ रहा है और मैं आपको फिगर्ज भी दे सकता हूं। हैंक यार्न लास्ट ईयर का जो हमने ओब्लीगेशन के तहत दिया, वह फिगर्ज मैं आपके सामने रखूंगा।

पूरी तरह से जो मिल मालिक नहीं दे रहे थे उनके खिलाफ 600 से ज्यादा केस रजिस्टर किये। उसका नतीजा यह हुआ कि तकरीबन 469.27 मिलियन केसीज का जो हमारा हैंक यार्न के ओब्लीगेशन के तहत था, हमने हासिल किया। हमारी जरूरत थी 15851 मिलियन स्क्वायर मीटर जो कपड़ा हमने तैयार करना था हैंक यार्न के जरिए से। मैं यह बताना चाह रहा था कि जिस तरह से भी आब्लीगेशन के तहत जो मिलों से हमको हैंक यार्न इश्यू करना है वह हमने मैक्सीमम हासिल किया है। हमारे पास और भी स्टाक है, उसमें कोई कमी नहीं है। हमारे आनरेबुल मेम्बर श्री प्रगदा कोटैया को मैं बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के डिसिजन के बाद पूरी तरह से अमल करके हैंक यार्न मिल मालिकों से लेने का काम हमने शुरू किया है। जो सिंथेटिक मिल्स हैं उनसे भी हम आब्लीगेशन ले रहे हैं। वे दूसरों से

खरीदकर लाकर आब्लीगेशन पूरा कर रहे है यह मैं अपने आनरेबुल मेम्बर्स को बताना चाहता हूं । उसमें कोई कमी नहीं है ।

यह बोला जाता है उपसभाध्यक्ष जी, कि आपने जो रिजरवेशन 22 आइटम्स का है, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसिजन आया है उसको क्यों नही अमल किया । फौरन अमल, जैसे ही शुरू किया तो सारे देश के जितने भी पावरलूम के लोग थे वे आए, रिप्रेजेंट किया कि सारे पावरलूम्स बंद हो रहे हैं, इसका क्या करेंगे । उसके बाद इन्हीं हमारे आनरेबुल मेम्बर्स से पूछकर हमने एक सलाहकार कमेटी पावरलूम मिल और हैंडलूम वीवर्स के प्रतिनिधियों को मिलाकर बनाई ।

SHRI PRAGADA KOTAIAH: Sir, I would like to...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): No query. Please take your seat. I will permit you later on.

SHRI PRAGADA KOTAIAH: Sir,...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Please resume your seat. (*Interruptions*). Nothing will go on record. I will give you one or two minutes later on. Mr. Minister, please continue.

श्री जी० वेंकट स्वामी : तो उस आब्लीगेशन को पूरा करने के लिए हमने एडवाइजरी कमेटी बनायी जिसमें हमारे आनरेबुल मेम्बर नोमानी साहब और प्रगदा कोटैया साहब और अन्य बहुत सारे मेम्बर्स भी हैं, वीवर्स भी हैं, हैंडलूम, पावरलूम के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं । सारा हिन्दुस्तान फिरा है इन लोगों ने। रिपोर्ट अभी सबमिट की है । जैसा कि नोमानी साहब ने कहा कि मीटिंग की है और अब दो-तीन महीने के अन्दर डिटेल में कितने आइटम्स बनते हैं–रियली ये 22 आइटम्स हडलूम वीवर्स बना रहे हैं या कुछ आइटम छूट रहे हैं, इतना ही इनको बताना है । उसके बाद सख्ती से उसका इंप्लीमेंटेशन होने का मैं हाउस को विश्वास दिलाता हूं । उसमें पीछे हटने की बात नहीं है । गवर्नमेंट जीती है तो अमल भी करना चाहती है । उधर पावरलूम को भी जिंदा रखना चाहती है, हैंडलूम को भी जिंदा रखना चाहती है । यही इन्टेंशन है गवर्नमेंट का इसके सिवाय कुछ नहीं है ।

अब प्राइसेज का सवाल है । आनरेबुल मेम्बर यह कह रहे हैं कि प्राइसेज काफी बढ़े हैं । मैं जानता हूं उपसभाध्यक्ष जी, आपको भी याद दिलाता हूं कि उन्नीस सौ नब्बे में स्टार्विंग डेथ्स सुनी । यह खबर हमारे सामने है । सारा देश उससे पागल था, परेशान था । 1992 और 93 , 1993 और 94 में जो रेट्स बढ़े हैं, नब्बे से भी ज्यादा रेट्स बढ़ गए हैं । मैंने क्या किया । मैंने सारे देश के मिल ओनर्स से अपील की कि आप इस मुसीबत में इनके लिए हैंक यार्न बनाकर दीजिए । वह रेट्स दीजिए ताकि वीवर्स को उसका फायदा पहुंच सके । उन लोगों ने 10 हजार मिलियन के. जी. हैंक यार्न हमको दिया है । एन. टी. सी. से मैंने हैंक यार्न तैयार कराकर उनको सप्लाई किया है । नाट ओनली दैट, हिस्ट्री में देश आजाद होने के बाद, मैं आनरेबुल मेम्बर्स को बता देना चाहता हूं कि रेट्स काटन की वजह से नहीं बढ़े हैं हैंक यार्न के । हमारी जरूरत है 1 करोड़ 28 लाख बेल काटन की और हमारी कंट्री का प्रोडक्शन 1993–94 में 1 करोड़ 18 लाख बेल का हुआ जिसकी वजह से प्राइस हैंक यार्न का बढ़ गया । नाट ओनली दैट, हैंक यार्न का, कोन यार्न का भी रेट बढ़ गया है। उसकी बेसिक वजह है काटन की शार्टेज, उसकी वजह से हैंक यार्न और दूसरे यार्न के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं । तो उसको कंट्रोल करने के लिए, वीवर्स को फायदा पहुंचाने के लिए आनरेबुल मेम्बर मद्रास के भी कह रहे थे कि हैंक यार्न के रेट्स बढ़े हैं .....। वह यह मैं प्राइम मिनिस्टर से, फाइनांस मिनिस्टर से अपील करके 30 लास्ट ईयर लेकर पर के. जी. 15 रुपये का उनको रिलीफ दिलाया । मैं आनरेबल मैंबर्स से पूछना चाहता हूं कि क्या यह आज तक हुआ ? हमने अमल किया है और कर रहे हैं । नाट ओनली, उपसभाध्यक्ष जी, यह इस साल भी हमने किया है । . . . (**व्यवधान**)

श्री अनन्त राम जायसवाल : कितने दिनों के लिए ?

श्री जी० वेंकट स्वामी : जब तक कि यह चलेगा । उसकी कोई लिमिट नहीं है और वही नहीं बल्कि मैं खुशखबरी आपको सुनाना

चाहता हूं यह हमने किया है और इधर कॉटन का रेट घटता जा रहा है। 400 रुपये क्विंटल कम हुआ है। उसके बावजूद भी हमारी सबसिडी कंटिन्यू है। हम लोगों को दे रहे हैं। अब रहा असल झगड़ा . . . (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष जी, यह हैंक यार्न के बारे में ज्यादा तवज्जह नहीं है, सप्लाई नहीं हो रही है, यह बोल रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं हमारी तरफ से स्टेट गवर्नमेंट्स को हमारी पूरी स्कीम डिवेलपमेंट की वीवर को हैंक यार्न सप्लाई करने की स्कीम स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में रखी। एक नहीं, साल में तीन-चार मर्तबा मिनिस्टर्ज, आफिसर्ज स्टेट गवर्नमेंट के बुला-बुला करके इम्प्लीमेंट करने की हम कोशिश कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। वह लोग आगे बढ़ रहे हैं, शुरू-शुरू में मुश्किल हुआ है, मगर अब जो है लग गया है 6 महीना साल भर में, कुछ लेवल में क्या आवश्यकता है उनको जो बिलो पावर्टी लाइन हैं हम समझ रहे हैं वह ऊपर आने के बहुत सारे चांसेज हैं। असल सवाल प्रागदा कोटैया जी जो यहां उठाते हैं यार्न की जो है हमारे गुरुदास दासगुप्त जी बात करते हुए बोले . . . (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल) : यह तो कमेटी के मैम्बर हैं, वहीं क्यों नहीं सन्तुष्ट करते ? . . . (**व्यवधान**)

श्री जी० वेंकट स्वामी : अब यह तो उन्हीं से पूछिए, मैं क्या बोलूं। . . . (**व्यवधान**) . . . अब मैं गुरुदास दासगुप्त जी से कहना चाहता हूं . . . (**व्यवधान**)

SHRI PRAGADA KOTAIAH: He is referring to something else. What is this?.... ..(*Interruptions*)..He must answer that...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): He has understood your question...(*Interruptions*)...

SHRI G. VENKAT SWAMY: Mr. Kotaiah, I am coming to your point. You please sit down. ... (*Interruptions*)...

यह 130 मिलियन किलो यार्न एक्सपोर्ट हुआ था लास्ट ईयर में इस साल हमने उसको घटाकर 75 मिलियन कर दिया है, 40 काउंट का उसके अंदर कहा हैं कि यहां से ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। उसको बैन किया है। इससे खुश होने की बजाय क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, अरे, एक्सपोर्ट हो रहा है, गुरुदास दासगुप्त जी ने बताया कि कितनी मिलें बंद हुई हैं। अगर स्पिनिंग मिल बंद होते जायेंगे हैंक यार्न कहां से मिलेगा ? उसका भी तो बैलेंस करना हैं। . . . (**व्यवधान**)

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: The point is that yarn should be produced. But yarn should be utilised for domestic purpose. Most of the handloom sector mills...(*Interruptions*).

SHRI PRAGADA KOTAIAH: If we are not going to accept it now, when do we accept it? It is the competition from the powerloom sector that is responsible for the closure of the mills...(*Interruptions*)...

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: The Minister is avoiding two points. Number one is that there is short supply of yarn to the handloom sector. The second point is regarding price rise. These are the two basic factors along with marketing, credit and all that which are affecting the handloom sector. How is he going to attend to the problem of short supply of yarn and how is he going to stabilise prices? Our point is that since there is shortage of yarn, middlemen are stepping in and middlemen are increasing the prices. Short supply of yarn accompained by increase in prices is playing havoc with the handloom sector. He has not attended to this. Our objection is that when the country is starving because of shortage of yarn, why should there be indiscreet export of yarn? I am also against the export of yarn even to the extent he has assured. He has reduced it. But, why? Let us further reduce it.

SHRI PRAGADA KOTAIAH: In pursuance of the Textile Policy, the Government has spent Rs. 878 crores for modernisation of 317 mills in the private sector. Today 132 mills

are closed. With regard to NTC mills, the Government has spent an amount of Rs. 4,330 crores including Rs. 510 crores for modernisation of 120 mills. Today 75 mills out of 120 mills are under closure. The Annual Report of the Ministry has again stated that the powerlooms...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Mr. Kotaiah, don't you want answers to your questions?

SHRI PRAGADA KOTAIAH: In respect of looms in the mills the number of looms has come down from 2,10,000 to 1,50,000. The utilisation capacity is only 54 per cent. Earlier the mills were producing 5,000 million metres of cloth. They are now producing...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Mr. Kotaiah, please take your seat.

SHRI PRAGADA KOTAIAH: All this is because of competition from the powerlooms. The Minister will have to consider these aspects. Without considering them if you go on spending on mills, how can you do...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Please take your seat.

SHRI PRAGADA KOTAIAH: These are facts which you have stated in your own Annual Report.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): He will not reply to all of them. If you go on making a commentary, he will not be able to reply.

SHRI PRAGADA KOTAIAH: I am only restating what is there in the Annual Report.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Mr. Minister...*(Interruptions)*...

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, it is absolutely wrong to counterpose handlooms against mill sector. It is absolutely wrong. This is a parochial attitude and with this attitude no problem of the textiles industry can be attended to. I am absolutely against it.

श्री जी० वेंकट स्वामी : उपसभाध्यक्ष जी, गुरुदास दासगुप्त जी ने जो बात कहीं कि हैंक यार्न की सप्लाई नहीं है, मैं गुरुदास जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कहां सप्लायी नहीं है, वह जरा बता दें ? मैं आपसे कहता हूं कि सप्लाय ही नहीं बल्कि 20 रुपए पर के०जी० सब्सिडी देकर हम सप्लाई कर रहे हैं। अगर इसमें फर्क है तो आप जानकारी दीजिए, मैं आने के लिए तैयार हूं। मैं ऐसा काम करता हूं और अगर मुझे विश्वास नहीं है तो मैं नहीं बोलता। मैं हाउस को गुमराह नहीं करता। रेट बढ़ा है, यह सही है मगर मैं हाउस को इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहता हूं कि 8 दिन के अंदर यार्न का रोज-ब-रोज रेट घटता जा रहा है और उसके बावजूद हम 20 रुपए किलो दे रहे हैं।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: There is a shortage of yarn. There is a shortage of yarn everywhere, including West Bengal. I wish the hon. Minister was posted with facts.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): He will visit those places.

श्री जी० वेंकट स्वामी : आप मुझे एक लेटर दे दीजिए कि बंगाल में हैंक यार्न की सप्लाई नहीं हो रही है, मैं उसके लिए पूरी तरह से इंतजाम करने को तैयार हूं।

SHRI INDER KUMAR GUJRAL (Bihar): Sir, I have great respect for the Minister. I appreciate his concern...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Mr. Gujral, why are you standing?

SHRI INDER KUMAR GUJRAL: May I say one thing?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): But you have not taken my permission to speak. The Minister is replying to the debate.

SHRI INDER KUMAR GUJRAL: Sir, I am the Chairman of the Committee that the Minister is referring to. The Committee has examined the issue in great detail and submitted to this House a report in which grave anxiety about the shortage of hank yarn was expressed. I do hope my hon. friend has seen the report. I do hope my hon. friend will attend to it and I do hope he will remove the anxiety of his own Member sitting behind him who always tells me in the Committee that he feels that the handloom industry is dying.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Thank you.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Let the Minister be a little more responsible while making his statement or assertion in the House.

श्री जी० वेंकटस्वामी : उपसभाध्यक्ष जी, मुझे विश्वास है और हमारे ऑफिसर्स जो सप्लाय कर रहे हैं, अगर उसमें कोताही है तो मैं उस पर जरूर एक्शन लूंगा, मगर मैं आपको जरूर विश्वास दिलाता हूं कि मैं रोज-ब-रोज इसके ऊपर रात-दिन नजर रखे हुए हूं। बाकायदा ऑफिसर्स का पीछा कर रहा हूं। स्टेट गवर्नमेंट्स जहां-जहां इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, उसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश कर रहा हूं। इसके बावजूद ...(**व्यवधान**)...

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: You are always harping on one point: The State Governments are not doing. There is short supply of yarn and the short supply is because of short production. What has the State Government to do with it? It is the market condition. You are not accepting that position.

श्री जी० वेंकटस्वामी : मैं आपको रिस्पैक्टफुली यह बताना चाहता हूं कि हैंक यार्न की कंट्रीं को जितनी जरूरत है, उतना हमने हासिल किया है और यह मैंने स्टेटमेंट के पहले पैरा में कहा है और उससे ज्यादा हैंक यार्न हमारे पास है। अगर कहीं नहीं पहुंच रहा है स्टेट गवर्नमेंट की कमी की वजह से... (**व्यवधान**)...

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: That is the report of the Parliamentary Committee and the Parliamentary Committee consists of Members from all the parties. They have examined this.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Mr. Gujral has made a request to the Minister and he will see the report...(*Interruptions*).

SHRI V. NARAYANASAMY: Mr. Das Gupta, if you want to seek clarifications, you seek clarifications later.

श्री जी० वेंकटस्वामी : मैं गलत तथ्य नहीं बोल रहा हूं। ...(**व्यवधान**)... मैं जो कह रहा हूं, उसे सुनिए आप। यह सही है, उपाध्यक्ष जी, हाय हाय है। हमें देना है सोसायटियों को, जनरल जो सोसायटी के मैम्बर नहीं हैं उनको कैसे सप्लाई करेंगे ? मैंने रिपोर्ट में खुद दिया है। मोबाइल सिस्टम से भी इसकी सप्लाई करने का काम मैंने शुरू किया है। ... (**व्यवधान**)...

SHRI JIBON ROY: How much are you giving to those who are members of the cooperative societies?

SHRI G. VENKAT SWAMY: 23 per cent.

SHRI JIBON ROY: Then?

SHRI G. VENKAT SWAMY: That is why I started this mobile system to supply hank yarn. Is it wrong? (*Interruptions*)

SHRI INDER KUMAR GUJRAL: Sir, I hate to intervene and I repeat that my hon. friend is a very able Minister. I respect him for that. I also respect his concern for the poor. I have no doubt on these two points. But I think what he is saying today is not consistent with the facts as they prevail in the market. We have given a detailed report. As a matter of fact, today I am signing another report for this House on the Budget in which we have expressed anxiety once again that the shortage of hank yarn is universal, it is not only in one State but in every State. The weavers, be they in the cooperative societies or outside the cooperative societies, are faced with a very grave crisis.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): The Minister may assure the House that he will look into the report and the facts and see to it that remedial measures are taken. (*Interruptions*)

SHRI JIBON ROY:...and resolve the issue of....(*Interruptions*).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Everything cannot be resolved here and now.

श्री जी० वेंकटस्वामी : उपसभाध्यक्ष जी, हमारे आनरेबिल मैम्बर मिस्टर गुजराल ने जो बताया है, उसको मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं करता और गलत है, यह भी नहीं बोलता । मैं फैक्ट बता रहा हूं ...(**व्यवधान**)...हमने हैंक्यार्न सप्लाई जितना होना चाहिए कण्ट्री के लिए, उतना विद आब्लीगेशन हासिल किया है। फर्स्ट पार्ट और सेकेण्ड पार्ट, हम स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं, सप्लाई करते हैं, अगर वहां पर कुछ कमी है तो उसकी देखभाल हम करेंगे । यह इंपलीमेंटेशन आफ द हैंक्यार्न सप्लाई स्टेट गवर्नमेंट की रेस्पोन्सिबिल्टी है। मैं यहां स्टेट गवर्नमेंट की बात न करूं । मेरी मुसीबत यह भी है कि स्टेट गवर्नमेंट को भी देखना पड़ता है। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल) : नहीं आप यह कहिए कि जो पार्लियामेंटरी कमेटी की रिपोर्ट है उसको आप देखेंगे ही नहीं, उसको पढ़ेंगे भी और उस पर कार्यवाही भी करेंगे ।

श्री जी० वेंकटस्वामी : हां, मैं जरूर उसका विश्वास दिलाता हूं और हाउस को यह बता देना चाहता हूं कि आप मुझे मौका दीजिए ताकि यह जो वीवर्स के मसले को लेकर जो जो उनकी मुश्किलात हैं उन सबको दूर करूं । हैंक्यार्न सही तरीके से सप्लाई करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा । ...(**व्यवधान**)...

SHRI V. NARAYANASAMY: You have to balance the exports with the local demand. That is a very important point. You are exporting the hank yarn, but, on the other hand, there is a short supply here. So, you have to balance both. That is what you have to do. That is what we have been suggesting. You accept that.

SHRI G. VENKAT SWAMY: Already, I have told that... (*Interruptions*).

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: No further reduction. Let us seek the assurance of the Minister that in view of the fact that there is a shortage, he will further consider the question of:...(*Interruptions*).

SHRI V. NARAYANASAMY:... shortage and price increase, both.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Yes. Price increase and shrotage are inter-connected. Let him consider... (*Interruptions*).

श्री जी० वेंकटस्वामी : उपसभाध्यक्ष जी, इनकी बात को, इनके सजेशन को इसलिए मैं नहीं मानता कि हैंक्यार्न पैदा करने वाली मिलों को भी जिंदा रखना है। ...(**व्यवधान**)...

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: That is not the point.

श्री जी० वेंकट स्वामी : 130 मिलियन से निकाल कर इतना लाने के बाद सौ मिलें बंद हो गई । आप यही बोलते हैं। ...(व्यवधान) ... उधर मिल को भी जिंदा रखना है, इधर पावरलूम को भी जिंदा रखना है। ...(व्यवधान)...

श्री गुरुदास दासगुप्त : मिल को भी जिंदा रखना चाहिए, लेकिन डोमेस्टिक डिमांड जो है वह डोमेस्टिक डिमांड के कारण मिल जिन्दा नहीं होगा । ..(व्यवधान)... वह ठीक नहीं बोल रहे हैं।

श्री जी० वेंकट स्वामी : अच्छा ठीक है। मैं बोल रहा हूं, अभी ठीक । ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): The Railway Minister is here. He has to go back to the other House.... (*Interroptions*).

SHRI JIBON ROY: More than 200 million Kgs. has been exported.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Don't join issue with them. (*Interruptions*)

श्री जी० वेंकट स्वामी : उपसभाध्यक्ष जी, इनको क्यों टाइम दे देते हैं बीच में इंटरफीयर करने को? ...(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल) : आप कहकर खत्म करिए, न । ...(व्यवधान)...

SHRI PRAGADA KOTAIAH: How much you are going to give them... (*Interruption*).... How much harm is being done to the weavers. ..(*Interruptions*).

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल) : आप उनको बाहर ले जाइए और बाहर दोनों बात कर लीजिए ।

श्री जी० वेंकटस्वामी : उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे आखिरी बात कहता हूं, आनरेबिल मैम्बर के पूरे सजेशन मैंने सुन लिए हैं। हैंडयार्न पूरी तरह से सप्लाई करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा और उनकी जो मुश्किलात हैं उनको दूर करने के लिए पूरी कोशिश करूंगा ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): The discussion on the Calling Attention Motion comes to a close now. Now, I request the Railway Minister to move the Resolution.

I. THE BUDGET (RAILWAYS) 1995-96 AND

II. THE RESOLUTION APPROVING CERTAIN RECOMMENDATIONS CONTAINED IN THE NINTH REPORT OF THE RAILWAY CONVENTION COMMITTEE, 1991

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. K. JAFFER SHARIEF): Sir, I beg to move:

> "That this House opproves the recommendations made in paragraphs 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 and 65 contained in the Ninth Report of the Railway Convention Committee, 1991, appointed to review the rate of dividend payable by the Railway Undertaking to General Revenues etc., which was laid on the Table of the Rajya Sabha on the 15th March, 1995".

Sir, by a resolution adopted in the Lok Sabha on 16th September, 1991 and concurred in by Rajya Sabha on 17th September, 1991, the Railway Convention Committee, was constituted on 25th November, 1991. The Committee was appointed "To review the Rate of Dividend which is at present payable by the Railway Undertaking to General Revenues as well as other ancilliary matters in connection with the Railway Finance *vis-a-vis* the General Finance and make recommendations thereon."